● वर्ष-4
● अंक-01
रायपुर, शुक्रवार
09 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बायोटेक इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं...

भारतीय हॉकी टीम ने फिर जीता कॉस्य पदक

पेरिस। हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 52 साल बाद भारतीय टीम ने लगातार दो ओलंपिक में पदक अपने नाम किया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी टीम कांसा लाने में सफल रही थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई जो अंत में निर्णायक साबित हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का यह आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी है। भारत की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता।

भारत और स्पेन के बीच पहला क्वार्टर गोल रहित बराबरी पर रहा था। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने गोल कर बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि, दूसरा क्वार्टर खत्म होने से कुछ समय पहले ही हरमनप्रीत सिंह गोल कर भारत को बराबरी दिलाई। दोनों टीमों के बीच हॉफ टाइम तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर चल रहा था। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह ने भारत को बढ़त दिलाई।

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि, एक उपलब्धि जिसे आने वाली पीढियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में चमकी, कांस्य पदक जीता। ये और भी खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने अत्यधिक धैर्य दिखाया। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीयों का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी।

वक्फ बिल लोकसभा में पेश, हंगामा

संसद में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। जहां लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावार रहा। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने साफ तौर पर कहा कि उसका मकसद इस बिल के जरिए पारदर्शिता लाना है। यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश की। वहीं, वायुयान विधेयक पेश किया गया। दूसरी ओर राज्यसभा में भी आज विनेश फोगाट मामले को लेकर हंगामा देखने को मिला। वहीं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इतने नाराज हो गए कि वह कुर्सी छोड़कर चले गए। सौगत रॉय ने किया कंगना को थप्पड़ मारे जाने का जिक्र कर दिया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतविार को लोकसभा में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया और फिर इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। रीजीजू ने सदन में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' को पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का

विपक्ष ने किया विरोध, बिल को संसदीय समिति के पास भेजा

जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि विधेयक में किसी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तथा असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक में सारी ताकत जिला अधिकारी को देने की बात की गई है और सबको पता है कि एक जगह एक जिलाधिकारी ने क्या किया था। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को सरकार से अनुरोध किया कि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जाए। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में इस वर्ग को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दो प्रमुख घटक दलों जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे वक्फ से जुड़ी संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। हालांकि, तेदेपा ने कहा कि इस विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। जद(यू) के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में कहा, ''कई (विपक्षी) सदस्यों की बातों से लग रहा है कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी है। यह कैसे मुसलमान विरोधी है?''

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यों की सराहना करते हुए लोकसभा में कहा कि अगर सरकार के सभी मंत्री उनकी तरह हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाएगा। आजाद ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए यह टिप्पणी की।

पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराये जाने के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग को राज्यसभा में आसन की ओर से खारिज किए जाने के बाद विपक्ष ने बृहस्पतिवार को उच्च सदन से बहिर्गमन किया। इस दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों के अमर्यादित आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ यह कहते हुए आसन छोड़कर चले गए कि वह कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं।

पांच जिलों के पंजीयन कार्यालयों में पायी गई गड़बड़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन विभाग द्वारा अचल संपित्तयों के क्रय-विक्रय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन संपत्तियों के पंजीयन के दौरान दस्तावेज़ों के गलत मूल्यांकन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये हैं। विभाग के सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा 18 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रुपये की राजस्व हानि की पहचान की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित जिलों के जिला पंजीयक शुल्क की वसूली के लिए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। साथ ही संबंधित उप पंजीयक एवं जिला पंजीयकों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में स्थित 102 पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों में कर अवपंचन की रोकथाम और सतत् निगरानी

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई 1.02 करोड़ रूपए की राजस्व हानि की पहचान
संबंधित उप पंजीयक एवं जिला पंजीयकों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

के लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मुख्यालय में विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पंजीयन विभाग द्वारा अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन से वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग ने लगभग 2505.98 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक से मिली जानकारी के अनुसार सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिले के अधिनस्थ पंजीयन कार्यालयों में पंजीबद्ध दस्तावेजों की रेण्डम जांच की गई। जिनमें 18 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रूपए की राजस्व हानि पायी गई है। इन प्रकरणों में कम बाजार मूल्य का निर्धारण, इसके अलावा मुख्य मार्ग से लगी हुई एक ही खसरे की भूमि को दो दस्तावेजों के माध्यम से मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग के दर अनुसार अलग-अगल उप पंजीयकों से पंजीयन कराया जाना पाया गया है। साथ ही गाइडलाईन के उपबंधों के अनुसार मूल्याकंन नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क की छूट का प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के नाम से था उसके नाम से दस्तावेज का पंजीयन न किया जाकर अन्य व्यक्ति के नाम से दस्तावेज का पंजीयन किया गया है तथा औद्योगिक संपत्ति का 25 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। स्टाम्प शुल्क छूट का प्रमाण पत्र बैंक के लोन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से छूट का था परंतु उस प्रमाण का लाभ भूमि क्रय करने हेतु लिया गया है। स्टाम्प शुल्क छूट निजी भूमि के क्रय पर दिया गया है परंतु औद्योगिक इकाई द्वारा स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ भवन, शेड, मशीनरी हेतु लिया गया है।

प्रमुख समाचार

भूपेन्द्र हुड्डा बोले, विनेश को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए

नई दिल्ली। पहलवान विनेश फोगाट द्वारा पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनके संन्यास की घोषणा के बाद नई दिल्ली में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसके पीछे साजिश का संकेत दिया है और उसके कुछ नेताओं ने मांग की है कि पहलवान को राज्यसभा में मनोनीत किया जाना चाहिए। इसके बाद, विनेश की बहन बबीता फोगट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई कांग्रेस से सीखे कि आपदा में राजनीतिक अवसर कैसे तलाशे जाते हैं। यह बयान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा यह कहे जाने के बाद आया है कि विनेश फोगट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए और कहा कि यदि पार्टी के पास राज्य विधानसभा में संख्या बल होता तो वह अब तक ऐसा कर चुकी होती। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बबीता फोगाट ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढना कोई कांग्रेस से सीखे। एक तरफ देश और विनेश ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।

लगातार बदल रही बांग्लादेश में स्थिति

नई दिल्ली। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में होने की खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ तौर पर बताया कि शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना भारत पहुंची थीं। ऐसे में फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी जा सकते। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर देश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नजर है। विदेश मंत्री ने इस पर संसद में भी बयान दिया है। हम लगातार इसको लेकर कई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में जल्द से जल्द कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की कामना करते हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें। उनके हित में काम करें। लेकिन कितनी क्षति हुई है इसकी जानकारी या आंकड़े हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सुरक्षा को लेकर हमारे वहां के अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख

ढाका। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। बंगभवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद यूनुस समेत अंतरिम सरकार के सभी सदस्यों को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया था। अब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रो. मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पेरिस से ढाका लौटने के बाद हवाईअड्डे पर यूनुस का सेना प्रमुख वकार उज जमां, वरिष्ठ अधिकारियों और छात्र नेताओं ने स्वागत किया था। इस दौरान उन्होंने कहा, उनकी सरकार का पहला काम कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना, अव्यवस्था को नियंत्रित करना और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकना होगा।

मंदिरों-मठों को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पटना। बिहार सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, इन संस्थाओं को ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को अपनी अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। इस मामले पर बोलते हुए, बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा, सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन प्रकाशन के लिए बीएसबीआरटी को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी डीएम को एक पत्र भेजा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने बीएसबीआरटी को डेटा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए

फ्रंटलाईन मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर छापा भारत का गलत नक्शा

नई दिल्ली। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने कवर पेज पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के लिए फ्रंटलाइन पत्रिका चेन्नई के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परिषद मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। पत्रिका का अंक 10-23 अगस्त 2024 का है। एक बयान जारी करते हुए, परिषद ने कहा कि अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने 10-23 अगस्त, 2024 के अंक में कवर पेज पर गलत भारतीय मानचित्र दिखाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पत्रिका के संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गलत नक्शा दिखाए जाने को लेकर सरकार एक मसौदा लेकर आई थी। भू-स्थानिक सूचना बिल 2016 के मसौदे के मुताबिक़ भारत से जुड़ी कोई भी भौगोलिक जानकारी हासिल करने, प्रसारित करने, पब्लिश करने और वितरित करने से पहले सरकारी अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। इसमें कहा गया, किसी भी शख्स को इंटरनेट प्लेकटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विसेज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल फॉर्म में अंतरराष्ट्रीय सीमा सहित भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी को गलत तरीके से प्रसारित, पब्लिश और वितरित नहीं करना चाहिए।

अगस्त विश्व मूलनिवासी दिवस पर विशेष

भारत में तो सभी हैं मूल निवासी!

गिरीश पंकज

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त, 1982 को विश्व मूलनिवासी दिवस घोषित किया है। तब से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। नि:संदेह यह दिवस मनाना चाहिए. दुनिया में जो मूल निवासी है, उनका उन्नयन हो, इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है. लेकिन इस दिवस को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है, वह बेहद विचारणीय है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है की भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी है. लेकिन कुछ लोग यह भरम फ़ैलाने की कोशिश करते हैं कि भारत में आदिवासी आज जनजातीय या अन्य पिछडे वर्ग के लोग हैं, वही मूल निवासी हैं, बाकी जो है, वे विदेशी हैं यानी बाहर से आये हुए. इनमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय शामिल हैं. यह दुष्प्रचार एक तरह से सामजिक अलगाव पैदा करने वाला है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में 2007 में आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट किया था कि %%भारत देश में सभी मूल निवासी है%%. दरअसल 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाये जाने के पीछे एक बड़ा कारण है। उसको भी समझना ज़रूरी है। इटेलियन नाविक कोलंबस भारत की खोज में निकला था लेकिन भटक कर वह अमरीका पहुँच गया. वह तारीख 9 अगस्त ही थी. वहां पहुँचने के बाद उसने वहाँ के मूल निवासियों के साथ अत्याचार किए। अनेक मूल निवासी महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया. फिर उन्हें वेनिस के बाजार में बेच भी दिया. अनेक लोगों की उसने हत्याएं की.उसकी बर्बरता को लोग भूल गए, बस यही याद रहा कि कोलंबस ने अमरीका की खोज की, इसलिए अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 8 अक्टूबर 1993 में कोलंबस डे मनाने की भी घोषणा कर दी थी. इस दिन अवकाश भी घोषित कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त को मूलनिवासी दिवस मनाने की घोषणा कर कर दी. कायदे से तो इस दिन को नरसंहार दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए. भारत में इस दिवस को मनाने का कोई विशेष औचित्य नहीं क्योकि यहां जिनको हम मूल निवासी के रूप में चिन्हित करते हैं यानी जनजातीय बंधुओं को, उनके उन्नयन हेतु सरकार हर सम्भव कार्य कर रही है। आज भी वनप्रांतर में रहने वाले वनवासी बंधुओं के लिए अनेक लाभकारी योजनाएँ जारी हैं. यही जनजातीय बंधु अपनी सुविधा और स्वेक्षा से वनों में निवास करते हैं क्योंकि उन्हें प्राकृतिक जीवन पसंद है। वे शहरों में आ कर रहना नहीं चाहते लेकिन अनेक लोग धीरे-धीरे आ रहे है। आरक्षण का लाभ लेकर वे सरकारी नौकरी भी कर रहे है. जो लोग सदियों पहले वनो से निकल कर शहरों के आकर रहने लगे, उन्हें यह समझना कि वे विदेश से आकर यहाँ बसे, गलत स्थापना है। आर्य बाहर से आए, यह वामपंथी दुष्प्रचार वर्षों पुराना है. आर्य भी भारत के मूल निवासी है। आर्य यानी हिन्दू, सनातनी. भारत की वर्ण व्यवस्था में ब्राहमण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चिरकाल से ही रह रहे हैं ये कोई जातियां नहीं थी, वर्ण काम की प्रकृति के अनुसार यह व्यवस्था बन गई। हमारे यहां तो कहा ही गया है कि हर पैदा होने वाला व्यक्ति शूद्र ही है, बाद में वह अपने कर्मो के हिसाब से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र बनता है. जन्मना जयते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते. जिस मनु स्मृति की निंदा की जाती है. मनु स्मृति में ही यह लिखा हुआ है, जहां स्त्री की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं. खैर, विषयांतर हो जाएगा. महत्वपूर्ण है मूल निवासी पर विमर्श, जिसे लेकर समाज में भ्रम फ़ैलाने की कोशिश लगातार हो रही है। जनजातीय बंधुओं के बीच यह बात रखने का प्रयास होता है कि आप लोग ही मूल निवासी हैं आपसे इतर जो भी है, वे विदेशी है. कुछ लोगों के मन में यह बात घर कर गई है इसलिए कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसे हवा देने वाले लोग अराजक ही कहे जाएंगे.

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भारत सहित अनेक देशो में वनवासी बंधु निवास करते हैं मगर वे मुख्यधारा से आज भी कटे हुए हैं. उन पर ध्यान देना ही चाहिए. भारत में देखें तो दस करोड़ से अधिक आदिवासी निवास करते हैं. मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़, झारखण्ड प्रांत में इनकी संख्या काफी है। सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश में है. डेढ़ करोड़ से अधिक। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग पौने तीन करोड़ है और यहाँ आदिवासी लगभग नब्बे लाख है. यानी आबादी का कुल चौंतीस प्रतिशत। ये लोग आज भी बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और कवर्धा, गरियाबंद आदि क्षेत्रों के सुदूर वनो में निवास करते है। इनकी सुध लेने की ज़रूरत है। इनके लिए अनेक योजनाए भी लागू की गई है. इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास आदि की समुचित व्यवस्था हमारा कर्तव्य है। अन्य राज्यों में भी आदिवासी है. मणिपुर में कुकी और मैतेई जनजातियों के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी है. मूल निवासी दिवस पर यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इन दोनों जन जातियों के बीच सुलह हो. और दोनों के साथ न्याय हो. यही इस दिवस का लक्ष्य होना चाहिए. भारत में आदिवासी बंधुओं के प्रति सम्मान का भाव तो इसी बात से समझा जा सकता है कि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला आदरणीया द्रौपदी मुर्मू हैं.भारत जैसे देश में मूलनिवासी बनाम अन्य का भ्रम फ़ैलाने वालों का वैचारिक प्रतिवाद बहुत ज़रूरी है. यह असत्य है कि जो अनुसूचित जनजाति के हैं, वे ही मूल निवासी हैं. हालाँकि जनजातीय समाज के अनेक लोग यह स्वीकारने लगे हैं कि भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी है, कोई भी विदेशी नहीं है. वे सब भी हमारी तरह सनातनी परम्परा के हैं. दु:ख की बात यह है कि भोलेभाले आदिवासियों को ईसाई बनाने की मुहिम भी जारी है. इसे रोकना ज़रूरी है वरना आदिवासियों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा. वे अपनी जड़ों से कट जाएंगे. मूल निवासी दिवस पर यह चिंतन बहुत जरूरी है.

एसईसीएल कुसमुंडा खदान के करीब पहुंचा दंतैल हाथी

■ महिला पर किया हमला; इलाज के दौरान हुई मौत

कोरबा। एक दंतैल हाथी जंगल से भटक कर गांव के मुख्य मार्ग पर जा पहुंचा जहां एसईसीएल कुसमुंडा खदान के करीब तक जा पहुंचा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाथी शहर की इतने करीब मुख्य मार्ग तक जा पहुंचा। जहां हाथी गांव के अंदर गली में घूमता हुआ नजर आ रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली ग्रामीण महिला गायत्री बाई पर हाथी ने हमला कर दिया और वे गंभीर रूप से घायल हो गई। जहां गायत्री के परिजन उसे तत्काल लेकर निजी अस्पताल पहुंचे जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।

बताया जा रहा है कि दंतैल हाथी तड़के सुबह जांजगीर-चांपा जिले के पंतोरा जंगल से कोरबा के नराईबोध आमगांव रलिया पहुंचा। जहां नराईबोध निवासी घायल गायत्री के नाती अनमोल कुमार ने बताया कि उसकी दादी रोज की तरह गुरुवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकली हुई थीं। इस दौरान अचानक हाथी पीछे से आकर उनपर हमला कर दिया और वह बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। ग्रामीण सूचना पर मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए।

ग्रामीणों ने बताया कि हाथी की आने की सूचना के बाद लोग दहशत में हैं। वहीं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं, कई लोग हाथी के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए। कोई अपने मोबाइल में वीडियो बना रहा था तो कई लोग उसे खदेड़ने के लिए उसके करीब जा रहे थे। जिस वजह से हाथी गुस्से में इधर-उधर भाग रहा था।

वहीं, हाथी गांव में पहुंचने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुचीं और हाथी पर नजर बनाए रखी है। वहीं, ग्रामीणों को वन विभाग की टीम समझा रही है कि हाथी के करीब ना जाए। दंतैल हाथी काफी आक्रोशित है और एसईसीएल कुमुण्डा खदान के आसपास मुख्य मार्ग पर पहुच गया और हाथी मवेशियों को दौड़ाता हुआ नजर आया। वहीं, हाथी के करीब से बाइक सवार जान जोखिम में डाल कर आवाजाही करते नजर आए।

सूचना मिलते ही कोरबा डीएफओ और कटघोरा डीएफओ पहुंचे मौके पर पहुंचे और वन कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया ताकि हाथी शहर की ओर प्रवेश न कर सके। उसे रेस्क्यू कर जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया गया। वन विभाग की टीम हाथी पर निगरानी रखी हुई है। नरईबोध गेवरा बस्ती व आसपास के गांव में लोगों में दहशत का माहौल बन गया है।

डोलोमाइट खदान के लिए बिना जनसुनवाई किए दे दी अनुमति

■ बिफरे ग्रामीण पहुंचे जिला कार्यालय

सक्ती। सक्ती में डोलोमाइट पत्थर खदान की अनुमति देने का मामला फिर गरमाने लगा है। विरोध के बाद भी अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सक्ती के डुमरपारा गांव में खुलने वाले डोलोमाइट पत्थर खदान के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को पुनः जनसुनवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल, 15 दिन पूर्व सक्ती जिले के डुमरपारा गांव में डोलोमाइट पत्थर खदान खोलने की अनुमति के लिए जनसुनवाई रखी गई थी, लेकिन पंच-सरपंच और ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही अधिकारियों ने जनसुनवाई खत्म कर चलते बने। इस बात की भनक लगने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों की गाड़ी को रास्ते पर रोक को नारेबाजी शुरू करते हुए फिर से जनसुनवाई करने की मांग की। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें फिर से जनसुवाई करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों के तरफ से जनसुनवाई को लेकर कोई पहल नहीं हो रही है। ऐसे में बिना जनसुनवाई कराए ही पत्थर खदान खोलने की अनुमति देने की आशंका से ग्रसित ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पत्थर खदान के विरोध में नारेबाजी की।

भारी बारिश के कारण जर्जर मकान हुए धराशायी

लोगों के सिर पर मंडरा रहा है खतरा

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर पालिका निगम क्षेत्र के आजाद नगर और सोनामनी नेहरू कॉलोनी में एसईसीएल ने कर्मचारियों के लिए दो से तीन मंजिल मकान बनवाएं थे। जिसमें एसईसीएल में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे। लेकिन मकान की हालत को देखकर एसईसीएल ने अपने कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करवा दिया।ताकि कोई जनहानि ना हो।लेकिन खाली पड़े मकानों में लोग कब्जा करके रहने लगे।

मकान की हालत इतनी खराब थी कि मकान कभी भी गिर सकते थे। लेकिन मकान में रहने वालों को कोई डर भय नहीं था। इस बार लगातार 5-6 दिनों से झमाझम बारिश होने के कारण ये मकान गिरने लगे हैं। लिहाजा अब मकान में रहने वाले रहवासी एसईसीएल और नगर निगम से अपनी छावनी के लिए गुहार लगा रहे हैं।

रहवासी ज्योति ने कहा मेरे पति टीचर हैं और करीब साढ़े नौ बजे मकान गिरने का आवाज आया। हम लोग बाहर निकलकर देखें तो मकान सामने से बारिश की वजह से गिर रहा था फिर एक साहब आए और बोले की आप लोग अपना और कहीं व्यवस्था देखो। हम लोग कहां जाएं हम लोग तो काम के ही लिए तो यहां पर हैं।

रहवासी शांति बाई ने कहा पहले से ही मकान जर्जर था इस वजह से टूट गया मैं सुबह 7 बजे नहा रहा था।मेरी पत्नी अंदर में ही थी सो रही थी। उसके बाद साढे नौ के आसपास यह मकान गिर गया। कुछ लोग ये घटना सुनकर आए थे। बोल तो रहे थे कहीं और मकान देने के लिए। लेकिन अभी तक कोई भी खबर हम तक नहीं आई है।

वहीं कुरासिया सब एरिया मैनेजर ने बताया कि जो लोग मकानों में रह रहे हैं वो कब्जा किए हुए हैं।कई बार इनको नोटिस दिया जा चुका है।लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं।

कुरासिया सब एरिया मैनेजर अरुण सिंह चौहान ने कहा अब इस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए मकान को खाली करवाने के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग का सहयोग लेकर खाली करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे जितने भी जर्जर मकान हैं। उन सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

बारिश के कारण अब जर्जर मकानों में रहना मुश्किल है।और तो और अब ये मकान गिरने लगे हैं।ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो खुद से कब्जा किया हुआ मकान छोड़ दें ताकि कोई नुकसान ना हो।

मनरेगा में अनियमितता को लेकर महिला सरपंच बर्खास्त, सचिव निलंबित

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर, सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में लापरवाही और अनियमितताओं के मामलों में सख्त कदम उठाए गए हैं।

जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कैलाशपुर में हुई अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच रूपवती चेरवा को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पक्की नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था और इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। लेकिन गुणवत्ताहीन नाली निर्माण की शिकायत के बाद जिला स्तरीय टीम से अविलंब जांच कराई गई और गुणवत्ता हीन कार्य को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए थे। साथ ही जांच में दोषी पाए गए ग्राम पंचायत सचिव रामप्रकाश साहू को तत्काल निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि नाली निर्माण के कार्य की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी सहायक (असिस्टेंट टेक्निशियन) सुरेश कुर्रे को बर्खास्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। वहीं इस कार्य में मटेरियल सप्लाई करने वाले फर्म को भी ब्लैक लिस्ट में दर्ज कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, निर्माण एजेंसी के तौर पर सरपंच को भी अनियमितता का दोषी पाया गया। जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सरपंच पर कार्रवाई हेतु विहित प्राधिकारी एसडीएम सोनहत को पत्र भेजा गया। एसडीएम सोनहत राकेश कुमार साहू ने प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित से जवाब मांगा, तो सरपंच ने मामले में अपनी लापरवाही स्वीकार की, जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1 के तहत पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।

डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी योजना या निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी निर्माण एजेंसियों को समय सीमा के भीतर प्रावधानों के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्री बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, गहरी खाई में गिरी

सूरजपुर। बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरगा चौकी इलाके में नेशनल हाइवे-130 के ग्राम पुटा ताराघाट के पास यात्रियों से भरी बस और ट्रेलर में ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई। बस और ट्रेलर वाहन सड़क किनारे 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा। पहले यात्री से भरी बस गिरी, उसके बाद ट्रेलर उसके ऊपर जा गिरा। इस हादसे के बाद यात्रियों से भरी बस में चीखपुकार मच गई और देखते ही देखते राहगीरों के भीड़ एकत्रित हो गई।

बस में लगभग 35 लोग सवार थे, जहां कुछ लोग किसी तरह अपने से कांच तोड़ बाहर निकल आए। वहीं, कई लोग बस के अंदर ही फंसे रहे। घटना की सूचना मिलते ही 112 और मोरगा चौकी पुलिस मौके पहुंची और बस में फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस दौरान बस में कटघोरा वार्ड नंबर-3 निवासी एक 30 वर्षीय युवती अंजू रात्रे फंसी हुई थी, जिसे बाहर निकालने के लिए गैस कटर और अन्य उपकरणों का उपयोग कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। चौकी प्रभारी नवीन पटेल और 112 की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवती को बाहर निकाला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। एंबुलेंस की मदद से पूरी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी जनता बस सूरजपुर से बिलासपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान ट्रेलर वाहन ने ओवरटेक करने के फेर में बस को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। मोरगा चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को किसी तरह बाहर निकाला। वहीं, बस में फंसी युवती का चार घंटे तक रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। बस में सवार लगभग 12 लोगों को चोंटे आई हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं, दूसरी बस में यात्रियों को बैठकर रवाना किया गया। हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और ओवरटेक को माना जा रहा है।

पार्षद खुद उतरे नाले की सफाई करने

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के एक पार्षद का नाला साफ करते हुए वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पार्षद के इस वीडियो को खूब शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के पीछ निगम की बड़ी लापरवाही और जनप्रतिनिधी की पीड़ा है, जिसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी होगी।

दरअसल, दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 8 में सालों पहले बना एक नाले में 2 वार्डों का पानी निकलता है। नाले की बनावट सही ढंग से नहीं की गई, जिसके कारण बारिश में इस नाले का पानी वार्ड क्रमांक 8 के सड़कों और घरों तक घुस जाता है। नाले के गंदे पानी के कारण स्थानीय लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कई सालों से नाले में सुधार करने की मांग की है। लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं किया गया।

स्थानीय लोगों ने इस बारिश में फिर घर घुस रहे नाले के पानी से तंग आकर अपने पार्षद पर नाराजगी जताई। जिसके बाद पार्षद चंदन सिंह ध्रुव खुद इस नाले को साफ करने उतर गए। इस दौरान पार्षद का वीडियो बनाया गया जा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर नाले पर पार्षद को उतरने की आवश्यक्ता क्यों पड़ी ?

नाला साफ करने के वीडियो को लेकर पार्षद चंदन सिंह ध्रुव ने बताया कि वार्ड वासियों के दर्द को नकारा नहीं जा सकता है। नाले की समस्या यहां कई सालों से है और नाले के बनवाने के लिए ही जनता ने उसे वोट देकर पार्षद चुना था। पार्षद ने बताया कि परिषद की बैठक में कई बार उन्होंने नाले के मुद्दे को उठाया, लेकिन पास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन बात ही नही सुन रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एटीएम मशीन को उखाड़कर ले गए चोर

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के ग्राम जेवरा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की एटीएम मशीन को चोर उखाड़ ले गए। इस मामले में बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी अनुसार, वारदात रात के समय हुई है। गुरुवार की सुबह आसपास से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। आरोपी ने कटर के माध्यम से मशीन के आसपास कटाई की, फिर मशीन को निकालकर ले उड़े। एटीएम मशीन में रुपये के संबंध में बैंक से जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

दो बैग में मिली नशीली सिरप एक गिरफ्तार, दूसर फरार

दुर्ग। दुर्ग में रेलवे पुलिस नशे के कारोबार करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रेलवे यार्ड से नशीली सिरप की खेप बरामद की है। रेलवे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया। आरोपी के पास से दो बैग भरे सिरप बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दुर्ग जीआरपी प्रभारी भूपेंद्र राठौर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे यार्ड में दो आरोपियों के द्वारा नशीली सिरप की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पुलिस टीम को एक्टिव किया गया। रेलवे यार्ड में दो युवक बैग लेकर घूमते दिखे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक आरोपी बैग छोड़कर फरार हो गया। वहीं, एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। बैग की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में अलग-अलग कंपनी की नशीली सिरप मिली। आरोपी की पहचान पाटन मिल पारा निवासी प्रेम प्रकाश नेताम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 508 नशीली सिरप बरामद की है।

चपरासी ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पीटा

कोंडागांव। कोंडागांव के प्राथमिक शाला आड़काछेपड़ा में पांचवीं कक्षा के बच्चों को डंडे से पीटने का मामला सामने आया है। प्राथमिक शाला के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रितेश कोर्राम ने बताया कि उच्च प्राथमिक शाला के चपरासी पवन तलवार ने बच्चों को डंडे से मारा है। मामले की जानकारी मिलते ही सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी इरशाद अंसारी स्कूल पहुंचे और बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और चपरासी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष रितेश कोर्राम ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिभावकों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

पिता को बचाने वाली सुशीला का होगा सम्मान

जगदलपुर। नारायणपुर के झारागांव में रहने वाले सोमधर कोर्राम के ऊपर पांच अगस्त की रात को कुछ अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद घर में मौजूद बेटी ने हमलावरों से बिना डरे उनका सामना करने के साथ ही पिता की जान बचाई और आसपास के लोगों की मदद से घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए मेकाज रेफर किया गया। तीन दिनों तक चले उपचार के बाद घायल ग्रामीण की हालत को देखते हुए गुरुवार को उसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। मेकाज के डॉक्टरों ने बताया कि घायल सोमधर कोर्राम के छाती में कुल्हाड़ी लगने के बाद घाव बन गया है। यहां दूरबीन पद्धति नहीं होने के साथ ही पर्याप्त उपकरणों की कमी के चलते उसे रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। रायपुर जाने के बाद वहां पर इसके पिता का ऑपरेशन होने के साथ ही अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके कारण पिता को बेहतर इलाज मिल सकता है।

झोले से हसिया निकाल रहे बच्चे को सांप ने काटा

सक्ति। हसौद गांव में रहने वाला अमन धनवार (13) घर के अंदर रखे एक झोले से हसिया निकाल रहा था। झोले के अंदर बैठे सांप ने उसकी उंगली में काट लिया। अमन ने सांप काटने की जानकारी अपने माता-पिता को दी। परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान किशोर अमन ने दम तोड़ दिया। सांप का जहर शरीर में फैल चुका था। पुत्र की मौत से माता-पिता और परिजनों में मातम छा गया। मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, सांप को पकड़कर बोरी में भरकर रखा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरनपुर-जगरगुंडा में रोड पूरी, लौटेगी इमली बाजार की खोई पहचान

रायपुर/सुकमा। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से सुरक्षा बलों ने अरनपुर-जगरगुंडा सड़क को पूरा करने में सफलता हासिल की है।छत्तीसगढ़ के उग्रवाद प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा इमली की बिक्री के लिए एशिया का सबसे बड़ा बाजार है।सुरक्षा बलों का मानना है कि अरनपुर- जगरगुंडा सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जगरगुंडा एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े इमली बाजार के रूप में अपना पुराना स्थान हासिल करेगा।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि पहले, सुकमा में जगरगुंडा क्षेत्र इमली की बिक्री के लिए एशिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में लोकप्रिय था, लेकिन नक्सली गतिविधियों में वृद्धि के कारण बाजार ने अपना अस्तित्व खो दिया। ये क्षेत्र नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। लेकिन इस मिथक को तोड़ने के लिए पुलिस और फोर्स ने अपनी कमर कसी।इसके बाद सबसे पहले धुर नक्सल क्षेत्र में सड़क का निर्माण करवाया गया।ताकि सरकारी

योजनाओं के साथ स्थानीय लोग विकास से जुड़ सके।

आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने कहा यह सड़क स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी।स्थानीय आबादी को बाहरी दुनिया से जोड़ने का माध्यम भी बनेगी। सीआरपीएफ और पुलिस ने इस महत्वपूर्ण खंड के निर्माण के लिए व्यापक अभियान चलाया है। कई सुरक्षा कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है। इस महत्वपूर्ण सड़क को पूरा होने में लगभग 5-6 साल लगे हैं।

वहीं इस बारे में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।दक्षिण बस्तर के जगरगुंडा क्षेत्र को सभी दिशाओं से (उत्तर अरनपुर-जगरगुंडा, पूर्व दोरनापाल-जगरगुंडा, पश्चिम आवापल्ली-जगरगुंडा और दक्षिण से गोलापल्ली-किस्टाराम-जगरगुंडा) से जोड़ने के लिए सावधानीपूर्वक योजना के तहत काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत कार्य के प्रथम चरण में अरनपुर-जगरगुंडा सड़क का कार्य पूरा हो चुका है।

आपको बता दें कि अरनपुर-जगरगुंडा मार्ग को बनाने में कई जवानों ने शहादत भी दी है। इस सड़क को बनाने से पहले कच्चे रास्ते में प्लांट किए गए 56 आईईडी को निकालकर डिस्पोज किया गया।साथ ही साथ कई बार नक्सली हिंसा के कारण ठेकेदारों ने काम बंद किया।लेकिन फोर्स ने इस सड़क को चुनौती के तौर पर स्वीकारते हुए अपने सख्त पहरे में सड़क का निर्माण पूरा करवाया।

डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटारिया ने कहा सड़क निर्माण का उद्देश्य सिर्फ नक्सल विरोधी अभियानों में सहायता करना नहीं था, बल्कि यह लोगों को समर्पित है। पिछले कुछ वर्षों से सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त प्रयास से यह कार्य पूरा हो सका।अब सरकार के उपलब्ध कराये जा रहे संसाधन इस क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे और इसका परिणाम सर्वांगीण विकास के तौर पर सामने आएगा।

इस सड़क को बनाने के लिए कई जवानों और नागरिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में बुरकपाल में 25 जवान और तालमेटला में 76 जवानों की शहादत हुई। आपको बता दें कि जगरगुंडा में जहां तक सड़क बनी है, वो कभी नक्सली कमांडर हिड़मा का क्षेत्र हुआ करता था। इसे लोग नक्सलियों की पहाड़ी भी कहते हैं। क्योंकि यहां के चप्पे-चप्पे पर नक्सलियों की तूती बोलती थी।सड़क बनाने के लिए कुल 5 पुलिस कैंप बैठाए गए। वहीं 200 से ज्यादा आईईडी रिकवर की गई। चार फेज में इस सड़क का निर्माण किया गया है। साल 2014 में शुरु हुआ ये काम 2024 में जाकर पूरा हुआ है।

इस सड़क के बनने से यहां रहने वाले लोगों को आसपास के तीन जिलों में आवागमन करने में सुविधा होगी।स्थानीय लोग अपना धान और वनोपज आसानी से बड़े बाजारों में ले जाकर बेच सकेंगे।जिससे इन्हें बिचौलियों को कम दामों में अपना माल नहीं बेचना होगा।इसी के साथ सड़क बनने से सरकारी सुविधाएं जैसे पीडीएस, स्कूल, आंगनबाड़ी,स्वास्थ्य केंद्र दूर दराज के इलाकों में खुलेंगे।

संक्षिप्त समाचार

आवारा मवेशियों की समस्या पर प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी

रायपुर। आवारा मवेशियों की समस्या को

लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में गौ सत्याग्रह का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी अवारा मवेशियों को स्थ्रू और कलेक्टोरेट में बांधेंगे। बैज ने बताया, कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालेगी। कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रति लेकर रैली निकालेंगे। प्रभातफेरी निकालकर संविधान रक्षा की शपथ भी लेंगे।

हम साथ साथ संस्था की महिलाओं ने मनाया हरियाली पर्व

रायपुर। हम साथ साथ सामाजिक सेवा संस्थान ने होटल रायपुर प्राईड में हरियाली पर्व के अवसर पर सोलह श्रृंगार मिस एंड मिसेज ब्यूटी,डांस रैप वाक और क्वीज कान्टैस प्रतियोगिता का आयोजन किया । इस अवसर पर संस्था की अध्यक्षा मृणालिनी मिश्रा ने छ.ग.के प्रथम त्यौहार हरेली संबंधित सांस्कृतिक एवं पारम्परिक प्रथाओं की जानकारी दी। उपाध्यक्ष कणिका चौबे ने मित्रता पर भावनात्मक कविता एवं विचार रखे । ज्युरी सचिन दिव्या शुक्ला महासचिव निर्मला शर्मा एवं वैजन्ती ने सोलह श्रृंगार एवं मिसेज ब्यूटी शुचिता चौबे मिस ब्यूटी रजनी डांस में शोमा डे स्पेशल अपीयरेंस में सेजल को विजेता घोषित कर पुरस्कार दिया । संस्था के अन्य पदाधिकारीयों एवं सदस्यों ने भी प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अंजु शर्मा , नंदिनी दीवान शोभा त्रिपाठी, नमिता,नीतु शर्मा, रत्ना शर्मा पप्पी शर्मा, आंचल, श्वेता शर्मा, किरण शुक्ला, वैशाली, सरस्वती शुभा शर्मा सोनालिका शुक्ला,नामिनी शर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

महिलाओं में होने वाले हार्मोनल असंतुलन के लक्षण के बारे में प्राध्यापकों ने जाना

रायपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं वूमेन रिड्रेसल कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को गुरुकुल महिला महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्राध्यापको के लिए स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन ऊर्जा फाउंडेशन के जीत नांगरे ने महिलाओं में होने वाले हार्मोनल असंतुलन के लक्षण के बारे में बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म का असंतुलन होना, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, अधिक पसीना आना एवं प्रजनन क्षमता में कमी होना है इसके लिए उन्हें आयुर्वेदिक दवा लेनी चाहिए और यह दावा किस तरह काम करती है इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। यह कार्यक्रम कार्यक्रम अधिकारी डॉ रात्रि लहरी व डॉ वंदना अग्रवाल के मार्गदर्शन में सम्पन हुआ। इस अवसर पर डॉ सिमरन वर्मा, डॉ सीमा चंद्राकर डॉ, अनुराधा गुप्ता, डॉ आराधना सिंह, डॉ ज्योति अग्रवाल, तृप्ति त्रिपाठी, मान्य शर्मा डॉ देव श्री वर्मा, अवंतिका सोनी, डॉ रिंकू तिवारी, डॉ आदिति जोशी, डॉ टीनू दुबे, प्रीति साहू, डॉ अंकित चौहान, अंशिका दुबे, प्रियंका तिवारी, स्नेहा एवं रेणु ग्रीडियन उपस्थित थी।

खपरी गांव के लोगों को जर्जर सड़कों से मिलेगी मुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आज बालोद जिला के विकासखंड गुंडरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत खपरी ब के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणजन अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। सरपंच श्रीमती जनक बाई साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि ग्राम ईरागुड़ा से पायला पहुंच मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, जिससे राहगीरों को आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव की गलियां पक्की न होने के कारण बरसात में कीचड़ भरा रहता है। उन्होंने गांव में कला मंच बनाने और आश्रित ग्राम भोथीपार को स्वतंत्र पंचायत बनाने की भी मांग की। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गुंडरदेही में स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित है लेकिन भवन नहीं होने के कारण पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनकर शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की बात कही। साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया।

नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम 10 लाख से अधिक का गांजा जब्त

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैक्टर में शातिर तरीके से अलग चेंबर बनाकर गंजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर ट्रैक्टर से 103 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। यह मामला पुरुर थाना क्षेत्र के सोहतरा गांव का है। जानकारी के अनुसार, पुरुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक लाल रंग के ट्रैक्टर में छिपाकर बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी की जा रही है। जिसकी सूचना पर पुरुर पुलिस में सोहतरा गांव पहुंची। पुलिस की आने की भनक पाकर आरोपी ड्राइवर गांव के हनुमाम मंदिर के पास ट्रैक्टर छोड़ फरार हो गया। पुलिस ने जब बिना नम्बर प्लेट की एक लाल रंग की ट्रैक्टर की तलाशी ली। इस दौरान ट्रैक्टर में एक गुप्त चेंबर बना हुआ मिला, जिसमें छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था।

रिमझिम बारिश के बीच जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे आमजन

मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का किया शुभारंभ, जनदर्शन में बड़ी संख्या में हुआ मौके पर ही आवेदनों का निराकरण

रायपुर। जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों का एक बार फिर आमजनों में उत्साह दिखा, रिमझिम बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। इस बार एक और बात को लेकर लोगों में उत्साह दिखा वह हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरूआत की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आने वाले लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6 हजार 200 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रूपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रतीक स्वरूप 12 हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, श्री पी.दयानंद सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में

आमजन उपस्थित थे।

जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंची महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में यह योजना कारगर सिद्ध हो रही है। महिलाओं ने बताया कि बहनों की राखी इस बार शानदार रहेगी। भाईयों के लिए अच्छी मिठाईयां खरीदेंगे।

मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुन्द निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलको से भी मुलाकात की और उनकी हौसल अफजाई की। इन खिलाड़ियों ने बताया कि 20 से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल हुड बॉल में हिस्सा लेने दक्षिण कोरिया जा रही है।

रायपुर जिले के ग्राम पंचायत परसुलीडीह के सरपंच के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने परसुलीडीह के स्कूल भवन में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को जल्द से जल्द शेड निर्माण करने के निर्देश दिए। बलौदाबाजार जिले के डोंगरिया के किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केमिकल प्लांट से खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जल्द राहत दिलाने कहा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर शहर के चौरसिया कॉलोनी की 18 वर्षीय सना परवीन, ग्राम सेरीखेड़ी की निवासी कोमल लहरे, और धमतरी जिले के ग्राम कचना के निवासी ठगिया साहू को मोटराईज्ड ट्राई सायकल प्रदान किया। मुख्यमंत्री से बिलासपुर की रिशी अग्रवाल और बेमेतरा जिले की सिद्धका गोस्वामी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राखी के पूर्व मेरे लिए राखी लेकर आई है और आपने मेरे हाथों में राखी बांध दिया। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों का स्नेह मुझ पर है। रक्षाबंधन का तोहफा मैं आपको अनुकंपा नियुक्ति के रूप में जल्द प्रेषित करूंगा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बालोद निवासी श्री बोधन लाल ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि उनकी जमीन अंडा में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें भू-अर्जन की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने इस पर बालोद कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई कर भू अर्जन की राशि दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही भू अर्जन से प्रभावित अन्य लोगों को भी शीघ्र राहत देने के निर्देश दिए।

रायपुर के फाफाडीह के रमण मंदिर वार्ड से आए रोशन साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका बेटा 8 साल का लक्ष्य एस्ट्रॉफी ऑफ़ ब्लैडर बीमारी से पीड़ित है। इसके इलाज के लिए उन्हें अहमदाबाद इसके लिए नियमित रूप से जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी समस्या सुनकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चे की बीमारी के संबंध में इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब आसानी से उतर पाएंगे बड़े विमान

रायपुर। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अब लंबे-चौड़े विमान भी आसानी से उतर पाएंगे, और उड़ान भर पाएंगे। इन विमानों के परिचालन के लिहाज से रनवे का 966 मीटर लंबाई वाला विस्तारित हिस्सा चालू हो गया है। यही नहीं रनवे की पूरी लंबाई के लिए ष्ट्रञ्ज ढ्ढ्ढ लाइटें भी आज से चालू कर दी गई हैं।

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2284 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 3250 मीटर किया गया है, जिससे आज से परिचालन शुरू हो गया है। विस्तारित रनवे और सीएटी ढ्ढ्ढ लाइटों के लिए पहले ही सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा चुका है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से विभिन्न अनुमोदन शामिल हैं।

इस कमीशनिंग में रायपुर एयरपोर्ट की टीम ने असाधारण प्रयास किए हैं। विशेष रूप से 7 अगस्त को मौजूदा रनवे में परिचालन बंद होने के बाद इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों की टीम ने पूरी रात काम किया है। बारिश में भी काम जारी रहा और 8 अगस्त की सुबह पूरा हुआ। बारिश के कारण एयरपोर्ट पर परिचालन में एक घंटे की देरी हुई।

सुचारु परिवर्तन और बेहतर समन्वय के लिए इंडिगो एयरलाइंस के निदेशक (संचालन) एसपीएस नारली को विशेष रूप से नई दिल्ली से नियुक्त किया गया था। एयरपोर्ट निदेशक अपनी टीम के साथ, नियंत्रण टॉवर में उपलब्ध, पूरे संक्रमण की निगरानी की। पूरा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट निदेशक डॉ। एसडी शर्मा के नेतृत्व में पूरा हुआ।

दिल्ली से इंडिगो एयरलाइन की पहली फ्लाइट 6ई 2062 सुबह 09 ।01 बजे सफलतापूर्वक लैंड हुई। पहली उड़ान का स्वागत दो क्रैश फायर टेंडरों द्वारा वाटर कैनन सैल्यूट के साथ किया गया। दिल्ली, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और उत्केला से आने वाली इंडिगो, विस्तारा और इंडिया वन एयर की कुल 8 उड़ानें आरडब्ल्यूवाई की पूरी लंबाई में 1200 बजे तक सफलतापूर्वक उतारी गई हैं।

नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष चेक पर नहीं कर सकेंगे साइन

रायपुर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक में हस्ताक्षर का अधिकार खत्म होने को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि नगर पालिकाओं, पंचायतों में अब सीईओ चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। निकायों में बेहतर ढंग से काम हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इससे जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में अधिक ध्यान दे सकेंगे।

बता दें, कांग्रेस के शासनकाल में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष को अब चेक में साइन करने का अधिकार था। लेकिन यह अधिकार वापिस ले लिया गया है और सीएमओ को दे दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है।

वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल 16 अगस्त को पाटन एसडीएम दफ्तर में मवेशी बांधेंगे, इसे लेकर उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि सरकार आवारा मवेशियों की समस्या का निराकरण कर रही है।

जहां व्यवस्था में सुधार की जरूरत होगी, वह भी करेंगे। डिप्टी सीएम साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। अपनी सरकार में तो उन्हें इस समस्या की याद नहीं आई।

आगामी नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जल्द ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं दोनों प्रणालियों में कांग्रेस की जीत के दावों पर अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा में भी जीत का दावा किया था, दोनों चुनावों में जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो किया उसे जनता भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी।

कोर्ट में महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर हुई सुनवाई

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगाने और पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है।

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है। प्रस्तुत याचिका में गया कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है। 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रदेश भर के निकायों में किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है।

राज्यपाल के हाथों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को मिली पीएचडी की डिग्री

रायपुर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के शोधार्थी रतन लाल डांगी (वरिष्ठ आईपीएस) ने बीआईटी भिलाई के ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रामेन डेका के हाथों डॉक्ट्रेट (पीएचडी) की डिग्री की प्राप्त की। बता दें कि डांगी ने अपना शोध कार्य निर्देशक डी। सुनीता मिश्रा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई एवं सहायक निर्देशक डॉ। प्रमोद यादव विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, सेठ आरसीएम कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग के निर्देशन में पूरा किया है।

आईपीएस डांगी के शोध का टॉपिक था छत्तीसगढ़ में माओवादी समस्या के उन्मूलन में सहायक पुलिस आरक्षकों की भूमिका (जिला बीजापुर के संदर्भ में)। ज्ञात रहे डांगी ने अपने कैरियर की शुरुआत देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग से ही की थी। वो एसडीओपी उत्तर बस्तर कांकर एसपी पश्चिम बस्तर बीजापुर, एसपी उत्तर बस्तर कांकेर, एसपी बस्तर, डीआईजी उत्तर बस्तर कांकेर एवं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पदस्थ रहे हैं। इन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरी समस्या माओवाद को नजदीक से देखा है एवं इसका मुकाबला भी किया है। जिला बीजापुर में पुलिस अधीक्षक रहते हुए नक्सलियों के विरुद्ध अभियानों का नेतृत्व करने से उनको राष्ट्रपति द्वारा दो बार पुलिस वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

माओवादियों के विरुद्ध आदिवासियों का स्व स्पूर्त जन आंदोलन सलवा जुडूम के समय डांगी बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक थे। उस दौरान माओवादियों ने आदिवासियों के राहत शिविरों एवं सलवा जुडूम नेताओं पर लगातार हमले कर रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने स्थानीय युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। इन युवाओं (एमपीओ) के सहयोग से पुलिस ने सघन नक्सल विरोधी अभियान चलाया, जिससे नक्सलियों के बस्तर से पैर उखड़े। उनके समर्थकों ने विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की ,जिस पर सुनवाई में न्यायालय ने एसपीओ की नियुक्तियों को अवैध ठहराकर सरकार को तुरंत इनकी नियुक्ति को निरस्त करने के निर्देश दिए।

महतारी वंदन योजना की राशि से राखी त्योहार रहेगा शानदार

छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने सीएम को कहा थैंक्यू

रायपुर। मुख्यमंत्री आवास पर आज जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में महतारी और बहनें भी सीएम से मिलने पहुंचीं। सीएम से मुलाकात के दौरान बहनों ने सीएम धन्यवाद दिया। महिलाओं का कहना था कि राखी के त्योहार से पहले महतारी वंदन योजना का पैसा खाते में आने से उनको काफी खुशी है। सीएम से मुलाकात के दौरान महतारी और बहनों ने कहा कि सरकार से मिले पैसों से वो राखी और भइया के लिए मिठाई खरीदेंगी।

सीएम से मुलाकात के दौरान बहनों ने कहा कि सरकार ने हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। महतारी वंदन योजना के मिले पैसों से वो अब मिठाई और राखी खरीदेंगी। सीएम विष्णु देव साय को महिलाओं ने धन्यवाद दिया। महिलाओं ने कहा कि सरकार ने जो फैसला उनको आर्थिक रुप से मजबूत बनाने का लिया है वो काबिले तारीफ है। बहनों का कहना था कि वो अब वो छोटे मोटे खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती हैं। सरकार जो हर महीने पैसे देती है उससे उनका काम चलता है।

अंजना दास, सुनंदा साहू ने कहा महतारी वंदन

योजना का जब जब पैसा खाते में आता मन को बड़ी खुशी मिलती है। महतारी वंदन योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ खर्च करते हैं कुछ बचाते हैं। अब हम अपने जरुरी काम के लिए और छोटे मोटे खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। विष्णु देव साय सरकार ने बहुत अच्छी योजना शुरु की। इससे पहले इस तरह की योजना नहीं शुरु हुई थी।

महतारी वंदन योजना की छठी किश्त 1 अगस्त को सरकार ने जारी की। सरकार बनने के बाद से हर महीने साय सरकार हर महिला को एक हजार रुपए उसके खाते में डाल रही है। हर महिला को साल के 12 हजार रुपए मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मोदी की गारंटी के तौर पर प्रचारित किया था। मोदी की ये गारंटी जनता के बीच काम कर गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एकतरफा जीत मिली। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 10 सीटें मिली।

सरकार उद्योगों और आम उपभोक्ताओं के बिजली के दाम वापस ले : कांग्रेस

- सरकार के तुगलकी निर्णय से 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

रायपुर। बिजली के दामो की बढ़ोतरी, नगरी निकायो के अध्यक्षो के वित्तीय अधिकार की वापसी, आवारा पशुओ की समस्या, 14 अगस्त को संविधान यात्रा, विश्व आदिवासी दिवस पर नवीन आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से अधिक दिनों से राज्य की स्टील ईकाईयां बंद है जिसके कारण इन ईकाईयों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगो से जुड़े अन्य लोगो के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समाचार माध्यमों से हमें जानकारी मिली है कि उद्योगो के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मानने के लिये आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अडी हुई है।

उन्होंने कहा कि 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगो, आम आदमी की बिजली के दामो को बढ़ा दिया है। लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार गलत निर्णय है। घोषित

तौर पर सरकार का दावा है कि 8 प्रतिशत घरेलू बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दो माह से सभी के घर का बिजली बिल दुगुना आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो देश के बड़े उर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, वही के नागरिको और उद्योगो को महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ा रहा है। कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा और हमें ही महंगें दाम पर बिजली? उद्योगो की बिजली के दामो की पडोसी राज्यों से तुलना करे तो ओडिशा, जो सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करता है, उसकी बिजली दर लगभग 5 रूपये 10 पैसा से 5 रूपये 30 पैसा है। पश्चिम बंगाल, जो तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है, उसकी बिजली दर 5 रूपये है। झारखंड और जिंदल पार्क, जो अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, उनकी बिजली दर भी 5 रूपये है। छत्तीसगढ़ जो दूसरा सबसे इस्पात उत्पादक राज्य है, यहां की बिजली दर 7 रूपये 62 पैसा से 8 रूपये 50 पैसा है।

भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार चुने हुये जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही हैं। दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुये लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुये जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे है। कल ही सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार अब नगर पालिका, नगर पंचायतो में अध्यक्षों को चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार को वापस ले लिया। यह अधिकार अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दे दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आये है इसलिये दुर्भावना पूर्वक सरकार ने यह निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया है। इस विकराल समस्या पर कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई ठोस निराकरण करें। यदि इसका कोई समाधान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग (एसडीएम) कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों में खुले पशुओ को ले जाकर छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांवो वार्डो में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। देश के संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जायेगी। कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की सभी प्रदेश वासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार पिछले डेढ़ साल से राजभवन में लंबित है। अब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी है। हम सरकार से मांग करते है कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक जो पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा से पारित करवा कर राजभवन भेजा था, उस पर हस्ताक्षर करने राजभवन से आग्रह करे। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है फिर आदिवासियों का 32 प्रतिशत, एससी का 13 प्रतिशत, ओबीसी का 27 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस का 4 प्रतिशत अधिकार राजभवन में क्यों रूका हुआ है?

आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था का अहम फैसला

ललित गर्ग

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों यानी एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक, न्यायसंगत, समानतापूर्ण बनाने का सराहनीय कार्य किया है। न्यायालय के इस तरह के फैसले मिसाल ही नहीं, मशाल बन कर सामने आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र की विसंगतियों एवं विडम्बनाओं से मुक्ति की दिशाएं उद्घाटित हो रही है। यह फैसला कई बिल्कुल अलग-अलग वजहों से अहम माना जा रहा है। क्योंकि बड़ा सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसीलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी समुदाय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह वस्तुस्थिति नहीं थी, इस विसंगति को सुधार कर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायसंगत उपक्रम किया है। अब राज्यों एवं केन्द्र सरकार को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। इस ताजे फैसले के बाद अनेक राज्यों में जातिगत गणना की होड़ शुरू हो सकती है एवं राजनीति दलों में आरक्षण का मुद्दा नये आक्रामक रूप में उभर सकता है। लेकिन एक आदर्श समता, समानता एवं संतुलनमूलक समाज-व्यवस्था को निर्मित करने की दिशा में कोर्ट का यह फैसला अहम है। संविधान पीठ के अनुसार, आरक्षण का मुख्य मकसद आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है, पर इसके लिए शहर और गांव की सामाजिक हकीकत में अंतर के साथ आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। एससी समुदाय में भी दो बड़े वर्ग है, जिनमें गहरा फासला है। बड़े अफसरों और बड़े वकीलों के बच्चों की तुलना में मैला ढोने वाले बच्चों से करना कैसे न्यायसंगत हो सकता है? इसलिए पीछे रह गई जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए ओबीसी की तर्ज पर एससी में भी कोटे के भीतर कोटे को न्यायाधीशों ने सांविधानिक माना है। आज के समय में इस फैसले की जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि देश में 140 करोड़ जनसंख्या की सामाजिक स्थिति और आर्थिक हैसियत के आंकड़े स्पष्ट तौर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की मांग बढ़ने से सामाजिक और राजनीतिक विद्वेष बढ़ सकता है। क्या इस फैसले से राज्यों में मनमानी बढ़ सकती है? अब नौजवानों से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे रोजगार, कोचिंग, अग्निवीर, नीट, इंटर्नशिप, नकल और शिक्षा पर बहस के बीच इस फैसले से क्रीमीलेयर का मुद्दा फिर गरमा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका भी है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। वैसे भी अब तक देश में आरक्षण वोट बैंक को सुदृढ़ बनाने का हथियार बना रहा है और राजनीतिक दल इसका अनुचित लाभ उठाते हुए अपेक्षित समुदायों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचने दिया।

बांग्लादेश के हालात से बहुत संतर्क रहना होगा

अशोक मधुप

बांग्लादेश में महीनों से सुलग रही आरक्षण और सरकार विरोधी चिंगारी सोमवार को भीषण आग के रूप में फूटी। 300 लोगों की मौत के बाद सेना भी उग्र भीड़ को संभाल नहीं पाई। नतीजतन करीब डेढ़ दशक से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा है। शेख हसीना भागकर फिलहाल भारत आई हैं। सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। शेख हसीना ने इंग्लैंड की सरकार से शरण मांगी है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब प्रदर्शनकारियों ने देश के चीफ ऑफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़-फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने घर में मौजूद कार, फर्नीचर के साथ घर का सारा समान लूट ले गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कॉन समेत देशभर में कम से कम चार मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक डरे और सहमें हैं। वहां क्या हालात बनेंगे? वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर भारत को नजर रखनी होगी। ये भी देखना है कि सरकार कैसी बनता है? उसका भारत के प्रति नजरिया कैसा होगा? नई सरकार कहीं इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा तो नही देगी। उसका रूख पाकिस्तान और चीन संमर्थक तो नहीं होगा? भारत को अपने देश की सीमा को पूरी तरह बंद रखना होगा, ताकि वहां के हालात से डरे नागरिक अपने भारत में न आ सकें।

1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करने की मांग के साथ पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारी आखिर फिर से इतने हिंसक होकर सड़कों पर क्यों उतर आए। असल में हिंसा की यह नई लहर तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने असहयोग का आह्वान किया। इसमें लोगों से कर या बिजली बिल का भुगतान न करने और रविवार को काम पर न आने का आग्रह किया गया। सोमवार को जब कार्यालय, बैंक और कारखाने खुले, तो प्रदर्शनकारियों ने लोगों को काम पर जाने से रोकना शुरू कर दिया। सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू की परवाह किए बिना ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग इलाके में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी पर हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों व वाहनों में भी आग लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे पर अड़े रहे। 14 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्या आरक्षण का लाभ रजाकारों के पोते-पोतियों को मिलेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बयान के बाद, 'तुई के, अमी के रजाकार, रजाकार' के नारे लगाने शुरू कर दिए और हिंसा ज्यादा भड़क गई।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा गठित रजाकार क्रूर अर्धसैनिक बल था। रजाकारों ने मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के खिलाफ अत्याचार किया। आज भी यह शब्द वहां अपमानजनक माना जाता है। इसका इस्तेमाल देशद्रोहियों और अत्याचारियों के लिए किया जाता है।

बांग्लादेश में उथल-पुथल व तख्तापलट का इतिहास 1975 से शुरू होता है।हसीना के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों की हत्या कर दी गई। जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया। 1981 गेस्ट हाउस में घुसकर विद्रोहियों ने जियाउर रहमान की हत्या की। हालांकि, सेना का बड़ा तबका वफादार होने से तख्तापलट नाकाम रहा। 1982 रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुस सत्तार को हुसैन मुहम्मद इरशाद के नेतृत्व में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इरशाद राष्ट्रपति बन गए। 2007 सेना प्रमुख ने एक कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया, जो 2009 तक सत्ता पर काबिज रही। 2009 अर्धसैनिक बलों का विद्रोह.. में 70 लोगों की हत्या, इनमें से अधिकांश सैन्य अधिकारी थे।2012 सेना ने कहा, शरिया या इस्लामी कानून से प्रेरित तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया है।

स्पष्टतौर पर बांग्लादेश में सुलग रही हिंसा के केंद्र में आरक्षण है। बांग्लादेश की जनसंख्या17 करोड़ है और देश में लगभग 3.2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं।1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के वंशजों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं। इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे लोगों के वंशजों को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। 10 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए भी है।

अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर पांच प्रतिशत व विकलांगों को एक फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़े जिलों में रहने वालों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।बांग्लादेश में बेरोजगारी से परेशान युवक इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार, हसीना के रिश्ते में बहनोई हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार वहां सबसे अहम चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने ही शेख हसीना के देश छोड़कर जाने और इस्तीफे का एलान किया। 20 दिसंबर, 1985 को बांग्लादेश की सेना में शामिल हुए जनरल वकार की छवि एक बेहद अनुशासित अधिकारी की रही है। जानकारों का मानना है कि हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना और वकार का कमान संभालना एक सोचा-समझा निर्णय है। शेख हसीना के देश छोडने के बाद देश के सेना प्रमुख ने कहा है कि वो सभी से बातचीत करके देश में अंतरिम सरकार बनवाएंगे! बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले सत्तारूढ़ रही आवामी लीग पार्टी ने आरोप लगाया है कि देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का हाथ है। आवामी लीग के मुताबिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग दिखाती है कि विरोध-प्रदर्शनों के पीछे असल में छात्र नहीं, देश के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल- बीएनपी और प्रतिबंधित संगठन- जमात-ए-इस्लामी की रणनीति है। इनका मकसद किसी भी तरह से देश की सत्ता हासिल करना है।

बांग्लादेश में देशव्यापी आंदोलन के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। खालिदा जिया विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख हैं और 1991-96 और 2001-06 के दौरान दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। राष्ट्रपति बोले- खालिदा जिया की रिहाई के बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा।

बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी नेताओं ने सोमवार को छात्रों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद देश में पैदा हुए हालात में किसी को भी लूटने का मौका न मिले, और उनसे अपनी मांगें होने तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया।

बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी है। देखना यह है कि बांग्ला देश में अब किसकी सरकार बनती है।उसका भारत के प्रति रूख कैसा होता है? नई सरकार भारत समर्थक होगी या कट्टर इस्लाम का रास्ता स्वीकार कर पाकिस्तान को अपना आका मानेगी।हालाकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार शेख हसीना के नजदीकी और रिश्ते में बहनोई लगतें हैं। उनसे उम्मीद है कि बांग्ला देश शेख हसीना के पद चिंहों पर चलेगा, किंतु वहां के राष्ट्रपति का रूख अभी देखना होगा।उसी रूख के आधार पर भारत को अपनी नई नीति बनानी होगी।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अविशिष्ट-क्रम (भाग-5)

गतांक से आगे...

4-शिव (वायु) पुराण- वायु ने श्वेतकल्प के प्रसंग से अनेक %धर्मों का और रुद्रदेव के माहात्म्य का जिसमें वर्णन किया हो उसे ही वायुपुराण किंवा शिवपुराण कहते हैं जिसका श्लोक प्रमाण 24 हजार है। उपलब्ध शिवपुराण में यह लक्षण सर्वथा घटित होता है परन्तु पद्यसंख्या केवल 18 हजार के लगभग है, लक्षणोक्ति के अनुसार छ: हजार श्लोकों की कमी है। जान पड़ता है कि यह अंश या तो लुप्त हो चुका है अथवा शिवधर्म्म-पुराण नामक उपपुराण में भूल से सम्मिलित कर दिया गया है।

5-लिङ्ग पुगण- जिस ग्रन्थ में महेश्वरदेव ने आग्नेय कल्प को लक्ष्य करके और अग्निलिङ्ग में स्थित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-- पदार्थों की प्राप्ति का साधन बताया हो वही लिङ्गपुराण है। जिसकी पद्यसंख्या ग्यारह हजार है। उपलब्ध लिङ्गपुराण में उपर्युक्त लक्षण सर्वथा घटित होता है पद्यसंख्या भी प्राय: ठीक है।

6-गरुड़ पुराण- (क) जिस ग्रन्थ में विष्णु भगवान् ने गरुड़ कल्प के प्रसंग में विश्वरूप अण्ड से लेकर सब वृत्तान्त गरुड़ के प्रति वर्णन किया है वही गरुड़पुराण संज्ञा वाला है। इसकी पद्यसंख्या अठारह हजार है अथवा (ख) उन्नीस हजार है। उपलब्ध गरुड़पुराण में यह लक्षण अंशत: घटित होता है परन्तु पद्यसंख्या प्रेतकल्पसहित अन्यून ग्यारह हजार ही शेष है। वास्तव में इस पुराण का प्रमाण 18500 था, 500 के तारतम्य से ही मत्स्य और नारद पुराणोक्त प्रमाण में एक सहस्र का अन्तर है - ऐसा कई पण्डितों का मत है। **7-नारद पुराण**- हे प्रिय! सुनो, तुम्हारे प्रति नारदीय पुराण कहता हूँ। यह पुराण बृहत्कल्प की कथा संयुक्त पच्चीस हजार पद्यसंख्या वाला है। उपलब्ध नारद पुराण में बृहत्कल्प का सम्बन्ध तो तथैव मिलता है, परन्तु अन्यान्य पुराणों की भांति उक्त पुराग के भी अन्यून तीन हजार। **क्रमश: ...**

नागपंचमी

दिव्यांशी भदौरिया

सावन का महीना आरंभ हो चुका है। सावन के महीने के बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। सावन के माह में नाग पंचमी का त्योहार भी आता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इसके साथ ही उत्तम फलों की भी प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल नाग पंचमी 09 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। हालांकि, नाग पंचमी के दिन कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए।

लोहे की वस्तुओं का दान करने से बचें - नाग पंचमी के दिन भूलकर भी लोहे की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। क्योंकि लोहे का संबंध का नाग देवता से होता है। इसलिए इस दिन लोहे का दान करना अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को ग्रहदोष लगता है। इसलिए इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को ग्रहदोष लगता है। इसलिए इस दिन लोहे की वस्तुओं का दान करना वर्जित है।

दूध-दही का दान न करें- नाग पंचमी के दिन दूध और दही का दान करने से बचना चाहिए। इससे नाग देवता नाराज हो जाते है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन परेशानियां भी बढ़ने लग जाती है। ध्यान रहे इस दिन सफदे चीजों का दान करने से बचें।

नमक का दान करने से बचें- इस दिन नमक का दान करने से बचना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक, नमक का संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका स्वभाव कठोर होता है। नाग पंचमी के दिन नमक का दान करने से शनि का प्रभाव बढ़ सकता है।

तेल का दान न करें- नाग पंचमी के दिन भूलकर भी तेल का दान न करें। इसका संबंध कुछ ग्रहों से होता है और इस दिन तेल का दान करने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है।

काले वस्त्र का दान न करें- इस दिन काले वस्त्र के दान करने से बचना चाहिए। काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। इसे नाग देव से जोड़ा जाता है और इस दिन काले रंग के वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति को राहु और केतु दोष लग सकता है।

नाग पंचमी के दिन करें ये उपाय-

- काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करें।
- पूजा करते समय महामृत्युंजय का जाप करें।
- इस दिन गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें।
- चांदी या तांबे के नाग-नागिन का जोड़ा किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें।
- काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में काल सर्प दोष पूजा करानी चाहिए।

ब्रिटेन में दक्षिणपंथी दंगों का आतंक

शिवकांत

अवैध आप्रवासियों और शरणार्थियों का विरोध करने वाले दक्षिणपंथी गुटों ने गत सप्ताह लंदन और मैनचेस्टर समेत ब्रिटेन के 20 से अधिक शहरों में उग्र प्रदर्शन किये, जिनमें कई जगह दंगे हुए और 50 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हो गये। प्रधानमंत्री सर किएर स्टामर को आपातकालीन कोबरा समिति की बैठक बुलानी पड़ी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा और ऑनलाइन अफवाहबाजी और मिथ्या प्रचार को भी अपराध की श्रेणी में रखकर सजाएं दी जायेंगी।

दंगे होना ब्रिटेन में कोई नयी बात नहीं है। दो सप्ताह पहले लीड्स और पूर्वी लंदन में दंगे हुए थे। दो साल पहले लेस्टर में दंगा हुआ था, जो सोशल मीडिया पर फैली अफवाह से शुरू होने वाला पहला दंगा था। गत सप्ताह के दंगे भी सोशल मीडिया पर फैलायी गयी अफवाह से ही भड़के हैं। पश्चिमोत्तरी इंग्लैंड के तटवर्ती शहर साउथपोर्ट में 29 जुलाई को अफ्रीकी मूल के एक 17 वर्षीय किशोर ने बच्चियों की नृत्य और योग शिक्षा की क्लास में घुसकर तीन बच्चियों को चाकू गोदकर मार डाला तथा पांच अन्य बच्चियों और उन्हें बचाने वाले दो लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था।

उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर पुलिस उसका नाम और पहचान नहीं बता सकी क्योंकि ब्रिटिश कानून किशोर अपराधी का नाम और पहचान सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं देता। इस बर्बर हमले से फैले गुस्से और संताप के माहौल में कुछ यूट्यूबरों और अफवाहबाजों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि हमलावर मुस्लिम है, अवैध रूप से आया शरणार्थी है और जासूसी एजेंसियों की निगाह में रहा है। पुलिस द्वारा इसका खंडन करने पर भी अफवाह फैलती चली गयी। दंगाइयों को पुलिस के भेदभावपूर्ण बर्ताव से भी शिकायत थी।

अगली शाम को साउथपोर्ट के आसपास के दक्षिणपंथी गुटों ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों को शहर की मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जमा कर लिया। वहां शरणार्थी, आप्रवासी और इस्लाम विरोधी नारे लगे। लोगों ने पुलिस पर पथराव करना, बीयर की बोतलें और कूड़ेदान फेंकना शुरू कर दिया। अगले दिन दंगाइयों ने मैनचैस्टर के उस होटल को घेर लिया, जिसमें शरणार्थी आप्रवासियों को रखा जा रहा था। सबसे गंभीर हमला रोदरम शहर के एक होटल पर हुआ, जहां शरणार्थियों को रखा गया है।

लंदन में प्रधानमंत्री आवास के सामने दंगाइयों ने पुलिस पर फ्लेयर चलाये। इसी तरह बेलफास्ट, ब्लैकपूल, ब्लैकबर्न, लिवरपूल, लीड्स, हल, लेस्टर, ब्रिस्टल और हार्टलीपूल में उग्र प्रदर्शन हुए और कहीं-कहीं एशियाई ड्राइवरों को भी निशाना बनाया गया। हमलावर किशोर को पहली अगस्त को अदालत में पेश किया गया और जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे सजा सुनाने के साथ-साथ उसका नाम सार्वजनिक करने पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया। लेकिन तब तक पूर्वाग्रहों पर आधारित शक से उपजी अफवाहें अपना काम कर चुकी थीं।

इसी तरह दो साल पहले मध्य इंग्लैंड के शहर लेस्टर में पाकिस्तान पर भारत की एशिया कप विजय के जुलूस को लेकर कुछ जिहादियों ने सोशल मीडिया पर मस्जिद पर हमले की अफवाह फैला दी थी, जिसके कारण बर्मिंघम और लंदन से उग्र प्रदर्शनकारियों से भरी बसें लेस्टर गयीं और वहां हिंदू विरोधी दंगे किये। सोशल मीडिया के बहकावे में आकर लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण छह जनवरी को अमेरिका की संसद पर हुए हमले में देखने को मिला था।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिंसक अतिवाद संबंधी प्रयोगशाला में शोध करने वाली प्रो जूलिया एबनर का कहना है कि सोशल मीडिया के विविध मंचों की अलगोरिद्म सबसे विवादास्पद और उकसाने वाली बातों को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा कर उन्हें उलझाने के लिए ही बनायी गयी हैं। इसलिए इन मंचों पर झूठ की खुली छूट के होते हुए ब्रिटेन में इस तरह के दंगे होना स्वाभाविक था। गनीमत इस बात की रही कि अपने अतिवाद के लिए कुख्यात एक-दो नेताओं को छोड़कर किसी ब्रिटिश नेता ने या मुख्यधारा के मीडिया ने अपराधी और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर राजनीति या अटकलबाजी करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि भारत में होता रहता है। सरकार और विपक्ष ने न केवल सारी जिम्मेदारी पुलिस पर छोड़ी, बल्कि उसका सार्वजनिक रूप से पूरा समर्थन भी किया। भारत के सभी पक्षों को इससे सीख लेनी चाहिए।

दक्षिणपंथी नाइजल फराज और उनकी रिफॉर्म पार्टी के नेताओं ने जरूर प्रदर्शनों को आप्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ तथा उससे अंग्रेजी समाज की पहचान को मिलती चुनौती से जोड़ने की चेष्टा की, जिसकी हर तरफ से निंदा हुई। परंतु, इस चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप्रवासियों के नाम पर दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों का मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना संकेत देता है कि वे उन समुदायों को लेकर अधिक चिंतित हैं, जो यहां के समाज में समाकर चलने के बजाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करने पर आमादा रहते हैं। गत सप्ताह के प्रदर्शन और दंगे अधिकतर उन्हीं शहरों में हुए हैं, जहां 2011 में मुख्य रूप से एशियाई मुस्लिम समुदाय ने पुलिस के भेदभावपूर्ण बर्ताव के खिलाफ प्रदर्शन और दंगे किये थे।

ब्रितानी समाज में लोग भूलों से सबक सीखते रहे हैं। वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड के शहर डनब्लेन में टॉमस हैमिल्टन ने प्राथमिक स्कूल में जाकर 16 छात्रों और अध्यापिका को हैंडगन से गोली मार दी थी और बाद में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने हैंडगनों को लेकर ब्रिटिश समाज में ऐसी घृणा पैदा की कि डेढ़ साल के भीतर सरकार को हैंडगनों पर पाबंदी लगाने वाला विधेयक पारित करना पड़ा। पिछले सप्ताह भड़के दंगे सिद्ध करते हैं कि सोशल मीडिया में संवेदनशील मामलों पर झूठ की छूट और अफवाहबाजी हैंडगनों से कम खतरनाक नहीं है।

प्रधानमंत्री स्टामर ने कहा भी है कि उसे अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा। लेकिन क्या सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचने और इस पर कोई कानून बनाने का साहस कर पायेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसका संतुलन कैसे बैठाया जा सकेगा? पूर्व सोवियत नेता यूरी आंद्रोपोव ने कहा था कि मिथ्या प्रचार कोकीन की तरह है। एक-दो बार सेवन करना तो चलता है, पर यदि आप उसे हर समय लेने लगेंगे, तो लती बनकर पूरी तरह बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर हो रहा मिथ्या प्रचार लोगों में इसी तरह के बदलाव ला रहा है, जिसके संभावित प्रभावों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

आज का इतिहास

1916 कैलिफ़ोर्निया में लस्सेन ज्वालामुखीय राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया।
1925 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिज़ोरी को तोड़कर चार हज़ार रुपये लेकर फरार हो गए। यह घटना काकोरी षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है।
1942 अहमद कवाम तीसरे बार ईरान के प्रधानमंत्री बने।
1945 संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी, जापान में 70,000 से अधिक नागरिकों को मारने वाला दूसरा परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर 3 दिन पहले पहला बम गिराया गया था।
1945 द्वितीय विश्व युद्ध-यूएसएएएफ बमवर्षक बोक्सकर ने नागासाकी, जापान को तबाह करने वाले फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया।
1945 अमेरिका ने फैट नाम का दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया।
1945 मंगोलिया ने जापान से युद्ध की घोषणा की
1962 जर्मनी के शायर और लेखक नोबेल पुरुस्कार हरमैन हीसे का निधन हुआ।
1965 मलेशिया ने अपने सत्तारूढ़ दलों के बीच गर्म वैचारिक संघर्ष के कारण सिंगापुर राज्य को अपने महासंघ से निष्कासित कर दिया।
1971 समस्याग्रस्त-ब्रिटिश अधिकारियों ने गणतंत्रीय अर्धसैनिक सदस्यों होने का आरोप लगाते हुए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
1974 वाटरगेट कांड के कारण लगभग कुछ महाभियोग और निष्कासन से हटाने के कारण, रिचर्ड निक्सन पद से इस्तीफा देने वाले संयुक्त राज्य के एकमात्र राष्ट्रपति बन गए।
1974 राष्ट्रपति निक्सन के इस्तीफे पर उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के 38 वें राष्ट्रपति बने।
1988 वेन ग्रेट्ज़की को एडमोंटन ऑइलर्स से लॉस एंजेलिस किंग्स में सबसे विवादास्पद खिलाड़ी लेनदेन में से एक में शामिल किया गया था।
1989 तोशिकी कैफु जापान के प्रधानमंत्री बने।
1999 रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्तेपशिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख ब्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
2005 रोमुलस, मिशिगन में एक रासायनिक संयंत्र विस्फोट। किसी भी घायल की सूचना नहीं थी, हालांकि लोगों द्वारा निकट के घरों को खाली करने को कहा गया था।

शेख हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश में घुसने वाली थी इंडियन आर्मी

अभिनय आकाश

प्रणब मुखर्जी उन दिनों वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक रोज आधी रात प्रणब मुखर्जी के घर के फोन की घंटी बजी। फोन उठाने पर उधर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कंपकपाती आवाज में मदद मांगती नजर आई। संकट के दौर में शेख हसीना का पहले कॉल वैसे तो पीएमओ जाना चाहिए था। लेकिन प्रणब दा बंगाल से आते थे और उनकी हसीना से पुरानी जान पहचान थी। इसलिए उन्होंने सीधा उन्हें ही फोन मिलाया। प्रणब मुखर्जी को ये अंदाजा लग गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है। ये साल 2009 की बात है। लेकिन अभी तो 2024 का साल चल रहा है। सेना का देश के प्रधानमंत्री को पौन घंटे का अल्टीमेटम सामने आता है। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही है। आपके पास 45 मिनट है चाहे तो आप देश छोड़कर भाग सकती हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। 5 जुलाई को भारत अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर के हालात और जश्न की खबरों में डूबा ही था कि दिन भर की गहमा गहमी के बीच एक कोड एजेएएक्स 1431 सामने आया। ये बांग्लादेश की राजधानी धाका से उड़े सी-130 हर्कुलेस एयरक्रॉफ्ट का कॉल साइन था। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ती भीड़ और सेना के अल्टीमेटम के बीच ढाका से सेना का ही एक विमान उड़ता है और शेख हसीना को लेकर भारत के हिंडन एयरबेस पर लैंड होता है। बांग्लादेश में सरकार सेना के हवाले हो गई। सेना के ही नियंत्रण में अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।

शेख हसीना जब ढाका से टेकऑफ कर रही थी तो भारत के वायु सेना चीफ लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। इतना ही नहीं 2 राफेल विमान बिहार और झारखंड की सीमा से टेक ऑफ कर चुके थे। फिर जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर एक सेफ लोकेशन पर पहुंचने पर वो स्कॉट चला गया। भारत में लैंड करते ही उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से हो हुई । दोनों के बीच डेढ़ घंटे लंबी चर्चा भी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय हरेक गतिविधियों को लगातार मॉनिटर कर रहा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब शेख हसीना के मुश्किल वक्त में भारत बड़ा सहारा बनकर सामने आया हो। आज से डेढ़ दशक पहले तो भारतीय सेना शेख हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर चुका था। 26 फरवरी 2009 को शाम के वक्त कंवलदीप सिंह संधू अपना काम में लगे थे तभी एक कोड एक्टिवेट हुआ। ऑर्डर हुआ कि पैराट्रूप की एक पूरी बटालियन को तैयार किया जाए। पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर एक 1000 से ज्यादा भारतीय पैराट्रूपर ला दिए गए थे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जोरहाट

और अगरतला में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। यानी बांग्लादेश को पूरी तरह से घेरने की तैयारी हो चुकी थी। ये सारी तैयारी बांग्लादेश को लेकर हो रही थी। बांग्लादेश के पैरामिलिट्री फोर्स बीडीआर ने विद्रोह कर दिया था। भारत की योजना थी कि भारतीय सैनिक बांग्लादेश में तीनों तरफ से प्रवेश करेंगे और ढाका के जिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेजगांव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री के आवास गणभवन पर कब्जा करेंगे और हसीना को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। सेना की तैयारी के साथ ही भारत डिप्लोमैटिक स्तर पर भी स्थिति मजबूत करने में लगा था। भारत के तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन के राजनयिकों से संपर्क किया और उनसे हसीना को समर्थन देने की अपील की। लेकिन, फिर अचानक भारत ने बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं किया। अब सवाल ये कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। अविनाश पालीवाल ने अपनी किताब इंडियाज नीयर ईस्ट ए न्यू हिस्ट्री में बताते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे बांग्लादेश की संप्रभुता को ठेस पहुंचती। इसके साथ ही भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता था। इसके अलावा मौके की ताक में बैठे पाकिस्तान को भारत विरोधी एजेंडे को चलाने का अवसर मिल जाता। वैसे भारत के हस्तक्षेप से बांग्लादेश का इतिहाल पूरी तरह बदल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिर भी भारत ने हसीना को बचाने के लिए बल प्रयोग करने की धमकी देकर वहां की सेना को इतना कमजोर कर दिया कि हसीना अपने विरोधियों का सामना करने के लिए स्वतंत्र हो गई।

साल 2018 में मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके थोड़े ही समय बाद हुए आम चुनाव में कुल 300 सीटों में आवामी लीग को 257 सीटें मिली, जबकि विपत्र 26 सीटों पर सिमट गया। 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनाव में शेख हसीना को पता था कि इसका स्वरूप पिछले तीन चुनावों जैसा नहीं होगा। विपक्ष के 20-25 हजार नेता-कार्यकर्ता 2023 में हुए आंदोलन के दौरान जेल में थे। उनकी ओर से चुनाव बॉयकाट का नारा था। लेकिन लोग वोट देने आए इसके लिए आवामी लीग की ओर से ये बात फैलाई गई कि जो भी वोट नहीं डालेगा उसे कार्ड पर मिलने वाली कोई भी सरकारी सहायता आगे नहीं मिलेगी। इसके बाद भी वोटिंग बंद होने तक 28 फीसदी लोगों ने ही मतदान किया। बाद में चुनाव आयोग की खींचतान के बाद इसे 40 प्रतिशत बताया गया।

अभी वाले बवाल की शुरुआत जून में हुई, जब एक हाईकोर्ट ने 2018 में रद्द किए गए विवादास्पद कोटा सिटम को बहाल कर दिया। यह कोर्ट का फैला था, जिससे सरकार हाथ खींच सकती थी लेकिन शेख हसीना ने आंदोलन करने वा छात्रों को रजाकार और आतंकवादी घोषित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए आरक्षण को 79 पर ला दिया, लेकिन तब तक बात इतनी बिड़ चुकी थी कि मामला सरकार से माफी की मांग पर आ गया।

शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और फिर 2008 में वापस लौटी और सोमवार तक इस पद पर रही। 15 अगस्त, 1975 को उनके पिता और बांग्लादेश के पहले नेता शेख मुजीब रहमान की एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। उस रात 28 साल की हसीना अपनी छोटी बहन के साथ जर्मनी में थीं। हसीना वर्षों तक भारत में निर्वासन में रहीं, फिर बांग्लादेश वापस चली गईं और अवामी लीग अपने हाथ में ली। सैन्य शासकों ने उन्हें 1980 के दशक तक नजरबंद रखा। 1996 के आम चुनावों के बाद वह पहली बार प्रधानमंत्री बनीं। हसीना और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के बीच सत्ता संघर्ष चला। 2001 में हसीना हारी और विपक्ष की नेता बन गईं। 2008 में फिर चुनी गई और देश की इकॉनमी, इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। 2024 के चुनावों में हेरफेर के आरोप भी लगे, छात्रों के प्रदर्शन के चलते सत्ता गंवाई।

एक बार फिर से शेख हसीना ने इस संकट का समाधान भारत से अपने गहरे रिशतों में खोजने का प्रयास किया है। वैसे शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए भारत सरकार उन्हें समय देगी। भारत के सामने उन्हें लेकर दोहरी चुनौती है। बांग्लादेश की नई राजनीतिक हकीकत के मद्देनजर वह हसीना की अलोकप्रिय छवि से खुद को बचा कर रखना चाहेगा, साथ ही हसीना के साथ अच्छे संबंध के मद्देनजर उनके मदद मांगे जाने पर मददगार पड़ोसी का रोल भी उसे निभाना है। ऐसे में भारत इन दोनों मसलों को लेकर संतुलन बरतना चाहता है। यही वजह है कि भारत बेहद संवेदनशीलता के साथ साथ फूंक-फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेशी सेना के प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। इस बीच, पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दिए गए हैं। खालिदा को चीन और पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। हालांकि बांग्लादेश में जो भी सरकार आती है, भारत को उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ा सकता है।

कितनी बार अपने ही संस्थापक बंग-बंधु को मारेगा बांग्लादेश?

आरके सिन्हा

शेख हसीना का इस्तीफा बांग्लादेश के लिए एक दुखद अध्याय के रूप में याद किया जाएगी। उतनी ही दुखद वे तमाम छवियां हैं, जिन्हें सारी दुनिया टेलीविजन पर देख रही है। इनमें सैकड़ों लोग बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर चढ़कर उसे हथौड़े मारकर तोड़ रहे हैं। जिस बंगबंधु की कुर्बानियों के चलते बांग्लादेश का 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद जन्म हुआ था, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। मैं तो उन चंद युद्ध संवाददाताओं में एक था जिसने बांग्लादेश के 'राष्ट्रपिता' कहे जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के नेता शेख मुजीब के पराक्रम, चमत्कार और करिश्माई नेतृत्व को मुक्तिवाहिनी के संघर्ष से लेकर भारत-पाक के युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता तक नजदीक से देखा है। फिर यह भी देखा है कि 1975 में किस तरह उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों (विदेश में रह रही हसीना बच गई थीं) की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। अब उनकी बेटी और बांग्लादेश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाने वाली शेख हसीना को भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान, जो इस साल 23 जून से पद पर हैं, ने एक 'अंतरिम सरकार' का वादा किया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आदेश कौन देगा. उन्होंने विपक्षी दलों से बात की है. उन्होंने शेख हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को रिहा कर दिया है। खालिदा जिया के प्रधानमंत्रित्व काल में बांग्लादेश आतंकवाद का केंद्र बन गया था। खालिदा जिया घनघोर भारत विरोधी रही हैं. उनकी रिहाई से भारत की विदेश नीति को तय करने वाले चिंतित जरूर होंगे। खालिदा जिया जब अपने देश की प्रधानमंत्री थीं तब वहां टाटा ग्रुप की इनवेस्टमेंट करने की योजना का डटकर विरोध हुआ था। उसे हवा खालिदा की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ही दे रही थी। टाटा ग्रुप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा रही थी। टाटा ग्रुप को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बताने वाले भूल गए थे कि टाटा ग्रुप भारत से बाहर दर्जनों देशों में स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शितापूर्ण कारोबार करता है। वहां पर तो उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगाता। यह अफसोसजनक बात है कि बांग्लादेश में हिंदू कतई सुरक्षित नहीं हैं। जबकि बांग्लादेश में सदियों से बसे हिंदुओं ने बंग-बंधु के नेतृत्व में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। खैर, बांग्लादेश अब तो एक गहरे संकट में जा चुका है। अब इस बात की उम्मीद कम ही है कि वहां पर जिंदगी निकट भविष्य में पटरी पर लौट जाएगी। जो देश अपने संस्थापक का अपमान करता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है।

ट्रम्प की नस्लीय टिप्पणियां अमरीकी स्वभाव से हटकर

ऋतुपर्ण दवे

सच है कि दुनिया में कहीं भी राजनीति में कब कौन-सा नया अध्याय या घटनाक्रम जुड़ जाए, कोई नहीं जानता। 14 जुलाई को अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सभा में हमला, उसकी तस्वीरों से एकाएक उनके प्रति सहानुभूति भर गई। तनाव व आक्रोश भी दिखने लगा। यूं लगा कि यह चुनाव एकतरफा हो जाएगा क्योंकि डैमोक्रेटिक पार्टी का प्रचार भी एक पल के लिए थमता दिखने लगा।

ट्रम्प की छवि एकाएक हीरो की बन गई। उनके मुंह से निकला 'फाइट, फाइट, फाइट' हर जुबान और कपड़ों तक में छा गया। चुनाव से पहले ही रिपब्लिक पार्टी, डैमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी चुनौती देते दिखने लगी। कई वजहें पहले से थीं जो एकाएक उफान पर आ गईं। जहां मौजूदा राष्ट्रपति और डैमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी याददाश्त और कई हरकतों से चर्चाओं में आए और उनके कई वीडियो और मीम्स ने भी दौड़ में पछाड़ना शुरू कर दिया। इससे माहौल एकतरफा दिखने लगा। कहते हैं कि राजनीति शह और मात का खेल है। अमरीका में यही हुआ। हमले के केवल 6 दिनों बाद 20 जुलाई को जैसे ही जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस पर भरोसा जताया तो सब कुछ बदलने लगा। चुनावी संघर्ष बराबरी पर आ गया।

अब अमरीकी चुनावी परिदृश्य एकदम उलट दिख रहा है। जैसी नस्लीय टिप्पणियां अब डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं उसकी न केवल अमरीका बल्कि पूरे विश्व में आलोचना हो रही है। ब्लैक जर्नलिस्ट के एक सम्मेलन में बहस के दौरान ट्रंप ने कमला हैरिस को काली कहते हुए उनकी भारतीय पहचान पर भी सवाल खड़े किए। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में अमरीका में रहने वाले भारतीयों को यह नागवार गुजरा, गुजरना भी चाहिए। ट्रम्प कैसे भूल गए कि उन्हें पिछले चुनाव में भारतीयों ने कितना साथ दिया था? यह

भरोसा महज हैरिस की उम्मीदवारी से टूट गया? यकीनन ऐसी टिप्पणियां ट्रम्प की हताशा बताती हैं। चुनावी नतीजे क्या होंगे,यह अलग है। लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी अकड़ और गरूर के लिए पहचाने जाने वाले ट्रम्प ने कहीं खुद तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली?

महज एक पखवाड़े में ही हवा का रुख अपने खिलाफ तो नहीं कर लिया? इतनी जल्दी ट्रम्प कैसे भूल गए कि कभी उन्होंने एशियन-अमरीकन विरासत पर जोर दिया था। सही है कि कमला हैरिस पहली अश्वेत और एशियन-अमरीकन उप-राष्ट्रपति हैं। उनकी जड़ें भारत और जमैका से जुड़ी हैं। पढ़ाई ब्लैक यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से हुई। वह अश्वेत लोगों के अल्फा कप्पा महिला संगठन में सक्रिय रहीं। अमरीका जैसे विकसित और अलग सोच रखने वाले देश में ऐसी उम्मीद एक पूर्व राष्ट्रपति या भावी उम्मीदवार से नहीं की जा सकती। किसी को अधिकार भी नहीं कि वह चुनावी माहौल को पक्ष में करने हेतु या किसी की पहचान पर टिप्पणी करे या बताए। अब अमरीका में इसी पर गर्मागर्म बहसें हो रही हैं।

ट्रम्प की नस्लीय टिप्पणियां चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। यह उनकी न पहली टिप्पणी है, न आखिरी होगी। पहले भी उनकी नस्लीय भड़ास सामने आ चुकी है। सबको याद होगा कि बराक ओबामा पर भी झूठे आरोप लगाए थे कि वह अमरीका में नहीं जन्मे। अपनी ही पार्टी की लोकप्रिय नेता निकी हेली पर भी गलत आरोप मढ़े कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता-पिता अमरीकी नागरिक नहीं थे। निश्चित रूप से यह डोनाल्ड ट्रम्प की संकीर्णता का परिचायक है जो निजी टिप्पणियों से भी नहीं कतराते। संकीर्णता इतनी कि यह कहने से भी नहीं चूके कि लॉ की पढ़ाई के दौरान हैरिस पहली बार असफल हुईं व दूसरी बार में पास हुईं। कैलीफोर्निया के ओकलैंड में जन्मीं हैरिस की मां श्यामला का जन्म भारत में हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ीं और महज 19 की उम्र में अकेली अमरीका आ गईं। वह एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के साथ वैज्ञानिक भी थीं। वहीं उनके पिता जमैका में जन्मे थे।

डोनाल्ड ट्रंप का जिद्दी स्वभाव किससे छुपा है। बाइडेन के दौड़ से हटने को तख्ता पलट तो कमला हैरिस के लिए वह यह कहने से भी नहीं चूकते कि वह अमरीका में अपराध, अराजकता, अशांति और नरसंहार का कारण बनेंगी। निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रम्प के बेतुके बयान और खीझ ने हमले के बाद उमड़ी सहानुभूति को कम किया है। अब ट्रम्प की सत्ता वापसी में बड़ा रोड़ा बनती कमला हैरिस ने चुनाव को रोचक बना दिया। कहां कल तक बाइडेन की उम्र को लेकर ट्रम्प सवाल करते थे अब 78 वर्षीय ट्रम्प की उम्र को लेकर 59 वर्षीय हैरिस चर्चाओं में हैं। देखना होगा कि राजनीतिक और कूटनीतिक लड़ाई से ज्यादा मानसिक और स्वास्थ्य को लेकर अमरीका में कौन किस पर भारी पड़ता है। नस्लीय टिप्पणी, निजी हमले और भारत का उल्लेख कर ट्रम्प कहीं न कहीं अपना बड़ा नुकसान जरूर कर बैठे हैं।

पाकिस्तान को एक करारा जवाब होगा स्थिर जम्मू-कश्मीर

पूनम आई. कौशिश

5 अगस्त 2019, एक झटके में भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया तथा जम्मू-कश्मीर को दो संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने राज्य का भौगोलिक विभाजन किया और संपूर्ण देश में उनके इस कदम की सराहना की गई तथा पूरी घाटी को अभूतपूर्व सुरक्षा में लिया गया। 5 अगस्त 2024, यह 5 अगस्त, 2019 की 5वीं वर्षगांठ थी और राज्य में सितंबर में विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, विशेषकर इसलिए कि इस संघ राज्य क्षेत्र में बढ़ते आतंकवादी हमलों के चलते सुरक्षा परिदृश्य बिगड़ा है और इस वर्ष अब तक आतंकवादी हमलों में 50 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित संगठनों लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन व अन्य संगठनों द्वारा निरंतर संघर्ष जारी है, जिसमें आतंकवादियों ने अब तक शांत रहे जम्मू क्षेत्र को अपना खेल का मैदान बना दिया है और वहां पर वे बार-बार हमले कर रहे हैं।

वस्तुत: पिछले दो माह में घात लगाकर हमले करने की घटनाएं नियमित रूप से घट रही हैं और ये हमले विशेषकर पीर पंजाल के दक्षिणी भाग में हो रहे हैं, जहां पर लंबे समय तक आतंकी घटनाएं देखने को नहीं मिली थीं। हाल के हमलों में सेना के 2 अधिकारी और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, जिनमें से एक लश्कर-ए-तोयबा का विस्फोटक विशेषज्ञ था। उसके बाद पिछले सप्ताह राजौरी में सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें एक सैनिक घायल हुआ।

अधिकारियों के अनुसार 600 से अधिक उच्च प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादी कुपवाड़ा, डोडा, पुंछ और राजौरी की गलियों में छिपे हुए हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण हैं। बी.एस.एफ. प्रमुख और उप-प्रमुख को हाल ही में हटाया जाना सुरक्षा समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। यही नहीं, आतंकवादियों ने संघ राज्य क्षेत्र में नागरिक प्रशासन और पुलिस में भी घुसपैठ कर दी है और इसका प्रमाण यह है कि 2 सिपाहियों सहित 8 सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में निलंबित किया

गया है। यही नहीं, स्थानीय जिहादी स्लीपर सैल सक्रिय हो गया है और उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि बाहरी लोगों को वहां भूमि खरीदने और बसने की अनुमति दी जा रही है। इससे यह आशंका पैदा हो रही है कि विधानसभा चुनावों में और विलंब हो सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में समय सीमा निर्धारित की है।

आज घाटी का राजनीतिक क्षेत्र ऐसा बन गया है कि इसे पहचाना नहीं जा सकता। यहां तक कि यहां की स्थिति समझने वाले क्षेत्रीय दलों नैशनल कांफ्रैंस और पी.डी.पी. के पास भी 2019 के बाद कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और यही स्थिति भाजपा के स्थानीय नेताओं की है। नैशनल कांफ्रैंस के नई दिल्ली स्थित नेता सज्जाद लोन अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं रहे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि इंजीनियर राशिद जैसे नेताओं के पुन: उभरने को किस तरह रोका जा सकता है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत जेल में थे और जिन्होंने जेल में रहकर नैशनल कांफ्रैंस के उमर अब्दुल्ला को हराया। इस तरह के नेता क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के समीकरण बिगाड़ रहे हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि युवा और स्थानीय लोग इंजीनियर राशिद के साहसिक चुनावी कार्य से प्रभावित हैं। इन चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा और वह लद्दाख सीट हार गई, जबकि 2019 में उसने केवल यही सीट प्राप्त की थी। जम्मू की दो सीटों पर उसे 2019 की तुलना में कम वोट मिले हैं और यह सब तब हुआ जब संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से सरकार हर कदम उठाने के लिए स्वतंत्र थी। वह किसी भी तरह का प्रयोग कर सकती थी और प्रतिरोध या विरोध को दबा सकती थी।

आज स्थिति यह है कि घाटी सुरक्षित है और वहां पर पर्यटन खूब फल-फूल रहा है। वहां 21.3 मिलियन से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। निस्संदेह घाटी में आर्थिक और शासन के क्षेत्र में लाभ और सुधार हुआ है। सेवा प्रदाय में सुधार हुआ है। एक हजार से अधिक लोक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की बड़ी परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। तथापि जैसा कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि आर्थिक और प्रशासनिक उपायों के परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हमें आतंकवादी रोधी कार्रवाई में तेजी लानी होगी और युवाओं के कट्टरपंथ को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।

दृष्टि से लोगों ने चुनाव में विश्वास व्यक्त किया और इसका प्रमाण यह है कि राज्य में हिंसारहित मतदान हुआ और 35 बूथों में सर्वाधिक 58.6 प्रतिशत मत पड़े। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि घाटी में चेरी के फूल खिल रहे हैं। स्पष्टत: राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक सोची-समझी रणनीति की आवश्यकता है और इसे एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। केन्द्र को यह समझना होगा कि जम्मू-कश्मीर मुद्दे के समाधान में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए क्योंकि वे इसमें मुख्य हितधारक हैं और प्रशासन में लोगों की भागीदारी के माध्यम से अलगाव की भावना को समाप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर केन्द्र सरकार को दोहरी रणनीति अपनानी होगी। एक ओर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा और उनके घावों पर मरहम लगाना होगा, युवाओं को अलगाववाद से बचाना होगा और इसके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही आतंकवादियों का मुकाबला कड़ाई से करना तथा उनका सफाया करना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सुदृढ़ और स्थिर जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक करारा जवाब होगा और बहुलवादी हिन्दू भारतीय समाज और यहां फल-फूल रहे लोकतंत्र के लिए एक सौगात होगी। मोदी को भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने तथा कश्मीरियों को सही मायनों में यह अहसास कराने, कि वे भारत के हैं, के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए।

राज्यपालों को संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए

विपिन पब्बी

राज्यपालों द्वारा निभाई जाने वाली सक्रिय भूमिका, खास तौर पर गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में, कोई रहस्य नहीं है और विपक्ष के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसकी काफी आलोचना की गई है। हालांकि, केंद्र सरकार इसके बारे में बेपरवाह दिखाई देती है और उसने फिर से राज्यपालों से सक्रिय भूमिका निभाने और जनता से जुडने के लिए कहा है। पिछले सप्ताह राज्यपालों के एक सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे गरीबों और वंचितों से जुडने और राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि राज्यपाल का पद एक ऐसी संस्था है जो लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वे बिल्कुल सही थे लेकिन समस्या तब होती है जब इनमें से कुछ राज्यपाल खुद को राजनेताओं की भूमिका में रखते हैं जो निर्वाचित राज्य सरकारों को धमकाने और परेशान करने के लिए काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों को महीनों और सालों तक दबाए रखते हैं, अन्य लोग विशेष रूप से तब आपत्ति जताते हैं जब उनके अपने विशेषाधिकारों की जांच हो रही होती है और कुछ लोग सक्रिय रूप से राजनीतिक टोपी पहन कर परेशानी वाले स्थानों पर जाते हैं और यहां तक कि सरकार की आलोचना भी करते हैं। पंजाब के पिछले राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जैसे अपवाद हैं जो राज्य सरकार को बर्खास्त करने की धमकी देते थे क्योंकि वह उनके संदेशों का जवाब नहीं दे रही थी और यहां तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी भी देते रहे। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल 'आग से खेल रहे हैं'। पुरोहित ने एक बार स्वीकार किया था कि वे जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहने के बाद भी इसे छोड़ नहीं सकते। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में संबंधित राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच इसी तरह का टकराव हो रहा है। केरल सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 7 विधेयक अटके हुए हैं, जिनमें से दो 23 महीने से लंबित हैं और 15 महीने से अन्य 2 लंबित हैं। कुछ महीने पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य के वित्त मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाने के लिए कहा था क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के 'सुख का आनंद लेना बंद कर दिया' था! मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से उनकी सलाह को अस्वीकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल में जून 2022 से राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के पास 8 विधेयक लंबित हैं। देश ने तमिलनाडु में तमाशा देखा है, जहां राज्यपाल आर.एन. रवि ने जानबूझकर राज्य विधानसभा में अपने भाषण के कुछ अंश नहीं पढ़े और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा विधानसभा में उनका मजाक उड़ाया गया। दूसरी ओर, भाजपा शासित मणिपुर में, जहां पिछले कई महीनों से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और जहां बर्खास्तगी का मामला बनता है, राज्य सरकार, राज्यपाल और केंद्र सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। राज्यपाल का पद एक गरिमापूर्ण पद है और पद पर आसीन व्यक्ति को राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है, जिसकी भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है। संविधान ने राज्यपालों को कुछ शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन व्यापक सिद्धांत यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। राज्यपालों को विरोधी भूमिका नहीं निभानी चाहिए और उन्हें संविधान के तहत उनके लिए परिकल्पित भूमिका तक ही सीमित रहना चाहिए। दुर्भाग्य से न तो राज्यपालों की हाल की नियुक्तियां और न ही राज्यपालों के सम्मेलन से निकलने वाले संकेतों ने विश्वास जगाया है। शायद सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की भावना के अनुसार राज्यपालों के लिए सीमाएं निर्धारित करनी होंगी।

भारत में बायोटेक इंडस्ट्री का कारोबार हर साल करीब 11 अरब डॉलर का है। सरकार ने 2025 तक इसकी कैपेसिटी को 100 अरब डॉलर पहुंचाना तय किया है। इस वजह से इस सेक्टर में आगामी सालों में नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं।

बायोटेक इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं

हमारे देश में बायोटेक इंडस्ट्री हर साल 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में हर साल इसका कारोबार करीब 11 अरब डॉलर का है। सरकार ने 2025 तक इसकी कैपेसिटी को 100 अरब डॉलर पहुंचाना तय किया है। इस वजह से इस सेक्टर में आगामी सालों में नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके नजर आ रहे हैं। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अनुसार अगले पांच साल में इस सेक्टर में 7 से 8 लाख नई नौकरियां मिलने का अनुमान है। यानी हर साल एक लाख से भी ज्यादा नौकरियां यहां मिल सकती हैं।

जरूरत से कम प्रोफेशनल्स यानी मौके ही मौके

इस सेक्टर में कितना स्कोप है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश के 300 से ज्यादा संस्थानों से करीब 50 हजार बायोटेक प्रोफेशनल हर साल निकलते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में हर साल करीब 80 हजार प्रोफेशनल्स की जरूरत है। बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ले चुके छात्रों के लिए नौकरी के अवसर ड्रग एंड फार्मास्युटिकल, केमिकल, एनवायरनमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और बायो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हैं। इसके इलावा अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में रिसर्च साइंटिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, एनालिस्ट, सेफ्टी स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर उनके लिए अवसर हो सकते हैं। इसके अलावा देशभर में 100 से ज्यादा रिसर्च लैबोरेटरी हैं, जिनमें हर साल हजारों लोगों को नियुक्त किया जाता है।

कहां से कर सकते हैं कोर्स?

बायोटेक्नोलॉजी के यूजी और मास्टर कोर्स देशभर के संस्थानों में मौजूद हैं। साइंस स्ट्रीम में 10+2 कर चुके छात्र अंडरग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बीटेक कोर्स कुछ आईआईटी संस्थानों में भी उपलब्ध है। इसमें प्रवेश जेईई एडवांस के आधार पर मिलता है और हर सीट के लिए 100 से ज्यादा आवेदक होते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में बैचलर डिग्री ले चुके छात्र मास्टर कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। अधिकतर संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन मिलता है।

सैलरी

यूजी कोर्स करने के बाद एंट्री लेने वाले छात्रों का शुरुआती पैकेज 3 से 4 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। एक दो साल के अनुभव के बाद यह रकम 6 लाख से ज्यादा हो सकती है। मास्टर या पीएचडी डिग्री ले चुके छात्रों के लिए नौकरी के अवसर ज्यादा होते हैं और उन्हें पैकेज भी ज्यादा मिलता है। रिसर्च संस्थानों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को शुरुआत में ही 5 लाख रुपए तक का पैकेज मिल सकता है।

देश में हैं 800 से ज्यादा कंपनियां

देश में बायोटेक्नोलॉजी की 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा देशी-विदेशी संस्थाओं में भी छात्रों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं।कृषि, हेल्थकेयर व अन्य क्षेत्रों में बढ़ा उपयोग देश की 50 फीसदी से ज्यादा आबादी के जीवनयापन का जरिया कृषि है, लेकिन घटती पैदावार खाद्य सुरक्षा के लिए संकट है। बायोटेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से हालात में सुधार हो सकते हैं। हेल्थकेयर, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्री आदि में भी ये तकनीकें कारगर हो सकती हैं। बायोफार्मा सेक्टर अकेले ही देश की अर्थव्यवस्था में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान दे सकता है।

अगर आप वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेने का ख्वाब संजो रहे हैं इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं इन स्कूलों में दाखिले के लिए जाने वाले ऐसे टेस्ट के बारे में जिनको पास करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं।

दुनिया के बेस्ट बी स्कूलों में दाखिले के लिए दें यह टेस्ट

हर किसी का सपना होता है कि वह जिस स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण करें वह दुनिया के टॉप स्कूलों में से हो। अगर आप वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेने का ख्वाब संजो रहे हैं इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं इन स्कूलों में दाखिले के लिए जाने वाले ऐसे टेस्ट के बारे में जिनको पास करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। पहला जीमैट यानि Graduate Management Admission Test - GMAT और दूसरा जीआरई Graduate Record Examination - GRE। बहुत से स्टूडेंटस जीमैट और जीआरई की अहमियत और मान्यता को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल जीमैट एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है जिसे देकर आप दुनिया के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों के एमबीए, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी और मास्टर ऑफ फाइनेंस जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं जीआरई एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके जरिए सभी पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। ज्यादातर छात्र, जो कि विदेश से एमबीए करना चाहते हैं, जीमैट परीक्षा ही देते हैं। जीमैट एमबीए के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है।

क्या है दोनों में फर्क

जीमैट और जीआरई दोनों ही एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं की प्रकृति और सामग्री अलग-अलग होती है। जीमैट टेस्ट का स्कोर 5 साल के लिए मान्य रहता है। साल में किसी भी समय आप www.mba.com पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दुनिया भर में इसके 600 टेस्ट सेंटर हैं।

जीमैट का स्कोर 82 देशों के करीब 1600 संस्थान स्वीकार कर रहे हैं। भारत के 90 से ज्यादा बी-स्कूल जीमैट स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं।

जीआरई का बढ़ता चलन

कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जीआरई देने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका में बड़ी तादाद में बी-स्कूल जीआरई में हासिल किए अंकों के आधार पर ही दाखिला दे रहे हैं। वैसे तो जीआरई कंप्यूटर और पेपर-बेस्ड दोनों फॉरमेट में करवाया जाता है लेकिन भारत में यह सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड फॉरमेट में ही होता है। दुनिया भर के 1200 से ज्यादा संस्थान इस टेस्ट के स्कोर को स्वीकार करते हैं। इसे भी साल में अधिकतम पांच बार दिया जा सकता है। दो प्रयासों में कम से कम 21 दिन का गैप जरूरी हो।

कौन दे सकता हैं ये टेस्ट

वैसे तो इन परीक्षाओं को ग्रजुएट उम्मीदवार बैठ सकते हैं लेकिन विभिन्न संस्थानों का चयन का तरीका एक-दूसरे से अलग हो सकता है। एक साल में 5 बार जीमैट दिया जा सकता है। लेकिन दो प्रयासों के बीच में 16 दिन का अंतराल होना जरूरी है।

इंटरव्यू के दौरान अपनाएं यह ट्रिक्स

आज के दौर में जॉब पाना मुश्किल होता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत की होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने इंटरव्यू में पूछे सारे सवालों का सही जवाब दिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें जॉब के लिए बुलावा क्यों नहीं आया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते है, लेकिन ज्यादातर यह होता है कि आपसे संतुष्ट नहीं होते, या आप सवालों के जवाब इतने प्रभावी तरीके से नहीं दे पाते।

इंटरव्यू का मकसद सिर्फ कर्मचारी के बारे में जानने या उससे मिलने के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि कंपनी में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी इंटरव्यू के बहाने आपके बारे में भी बहुत कुछ जान लेते हैं। इसलिए किसी भी जगह इंटरव्यू देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इंटरव्यू में लेने वाले अधिकारियों पर अपना पॉजीटिव प्रभाव छोड़ सकें।

पहली कंपनी की बुराई ना करें

कई बार लोग इंटरव्यू के दौरान अपने पहले जॉब को कोसते है और संस्थान के बारे में जी भर कर बुराई करते है। इन बातों का इंटरव्यू लेने वालों पर निगेटिव असर होता है। असल में हर बड़ी कंपनी के नियम, स्ट्रक्चर और व्यवस्थाएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। इसलिए ऐसी बातों से जॉब न मिलने की आशंका बढ़ जाती हैं। जिनके साथ काम करते हैं, उन्हें कम न समझें जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो यह ध्यान रखें कि पहले के संस्थान में काम करने वाले किसी कैंडिडेट के बारे निगेटिव न बोलें। इंटरव्यू लेने वाले के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। कोई भी कंपनी हो वह ऐसे कैंडीडेट को ज्यादा तवज्जो देती है जो खुद से निकलकर टीम भावना को लेकर चलता है।

ध्यान न भटकने दें

इंटरव्यू के दौरान अपना ध्यान सिर्फ वहीं फोकस रखें। एक इंटरव्यू के दौरान दूसरे जॉब के बारे में न सोचें। इससे हो सकता है कि आपके आव-भाव में कहीं कोई कमी नजर आने लगे। इससे आप सवालों का सहज जवाब भी नहीं दे पाते। इंटरव्यू में गलती से भी किसी फोन कॉल को अटेंड न करें। इंटरव्यू के बाद आप भले ही कॉल बैक कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी कमरे से बाहर भी निकाल सकते हैं।

अतिरिक्त प्रयास करने से बचें

बहुत से लोग इंटरव्यू पैनल को खुद करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यह सही तरीका नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते है तो हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल को लगे कि आपमें अपने जवाब को लेकर आत्मविश्वास की कमी है, इस वजह से आप अपने जवाब पर बार-बार जो दे रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट के सेलेक्ट होने के चांस कम होते हैं।

फर्स्ट इंप्रेशन

इंटरव्यू के दौरान यह ध्यान रखें कि आपका पहला इंप्रेशन बहुत प्रभावी होता है। आपकी ड्रेस, आपकी एंट्री इंटरव्यू पैनल पर प्रभाव छोड़ते हैं। कोशिश करें कि पहले सवाल के जवाब देने के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेंज में आत्मविश्वास हो।

कंपनी के बारे में रखें जानकारी

इंटरव्यू से पहले ज्यादातर लोगों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती ।आपके पास कितनी भी स्किल्स हो या आपकी क्वालिफिकेशन्स आपको योग्य उम्मीदवार साबित करती हो लेकिन कंपनी के बारे में जानकारी न होना आपके लिए रेड सिग्नल साबित हो सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केजरीवाल की 20 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत याचिका को निस्तारित कर दिया और उन्हें राहत के लिए अधीनस्थ अदालत में जाने की छूट प्रदान की। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

एनसीपी के दोनों गुटों में सम्मान और स्वाभिमान की जंग

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने बुधवार को घोषणा की कि वह महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 9 अगस्त से शिव स्वराज्य यात्रा शुरू करेगी। यह घोषणा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट द्वारा 8 अगस्त से राज्यव्यापी अभियान जन सम्मान यात्रा शुरू करने से ठीक एक दिन पहले की गई है। एनसीपी के दोनों गुटों ने अपने पारंपरिक मतदाताओं तक पहुंचने के इरादे से नारों के साथ एक प्रोमो जारी किया। एनसीपी नासिक से अपनी रैली शुरू करेगी, वहीं शरद पवार का गुट जुन्नार के शिवनेरी किले से अपनी रैली शुरू करेगा, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। इससे एनसीपी के दोनों गुटों के बीच सम्मान और स्वाभिमान के बीच टकराव शुरू हो गया है। अजीत खेमे ने राज्य में एनडीए के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन सरकार द्वारा घोषित लोकप्रिय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विकासात्मक राजनीति की तर्ज पर अपना अभियान बनाया है।

जम्मू-कश्मीर चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला ने फिर उगली आग

श्रीनगर। देश ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने की पांचवीं वर्षगाँठ 5 अगस्त 2024 को बड़े धूमधाम से मनाई। लेकिन यह खुशी उमर अब्दुल्ला से देखी नहीं गयी। इसलिए वह एक बार फिर 370 हटाये जाने के खिलाफ झंडा बुलंद कर मैदान में उतर गये हैं। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद नया और समृद्ध जम्मू-कश्मीर बनाने के भाजपा के दावों को लेकर उस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा, मैं यह पूछने के लिए मजबूर हूं कि लोगों को पिछले पांच वर्षों में क्या मिला है। कठुआ जिले के नगरी में एक रैली को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, वे (अनुच्छेद 370 हटने के बाद) नया और खुशहाल जम्मू-कश्मीर बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन जमीनी स्थिति बिल्कुल विपरीत है और यही कारण है कि वे हार के डर के कारण आज तक विधानसभा चुनाव नहीं करा सके।

भू-माफिया के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई : सीएम योगी

अंबेडकरनगर/लखनऊ। दो दिवसयीय अयोध्या दौरे के बाद एक दिवसीय दौरे पर अम्बेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने जनपद में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची थानों में लगाई जाए। साथ ही नकल, पशु, खनन और भू-माफिया आदि पर प्रभावी कार्रवाई करें। जनपद में भय मुक्त वातावरण बनाए रखें, महिलाओं की सुरक्षा पर शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को पुन: क्रियाशील करें। जनपद स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई- संवाद सुनिश्चित करें। आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय। उन्होंने कहा कि त्रिनेत्र अभियान का सफल क्रियान्वयन करते हुए प्रत्येक निकाय एवं ग्राम पंचायत पर इसे पहुंचाना एवं जोड़ना है।

अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य : नीतीश

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए। राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी 'पंजीकृत मंदिरों/मठों' से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बीएसबीआरटी बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है। बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को कहा, ''सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए।''

विपक्ष के आरोपों से आहत हुए सभापति, कुर्सी छोड़ चले गए

धनखड़ ने कहा- मैं अपने आपको यहां सक्षम नहीं पा रहा, विनेश फोगाट मामले पर राज्यसभा में हंगामा

नई दिल्ली। देश के उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन के सभपति जगदीप धनखड़ नाराज होकर कुर्सी से उठकर चले गए। वे विपक्षी दलों के नेताओं की नारेबाजी से नाराज थे। उन्होंने कहा कि आज यहा जो हुआ, वह ठीक नहीं है। यहां मुझे नहीं, बल्कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। विपक्ष के नेता मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहा है। मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसे में में इस कुर्सी पर बैठने के लिए खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूं। इस बीच विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे सदन में विनेश फोगाट के मुद्द को उठाना चाह रहे थे। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। इस पर ही सभापति नाराज हो गए।

विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने के लिए अनुमति दी। उन्होंने खरगे से पूछा आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर खरगे ने कहा की हमने कल भी यह बात रखी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह सिर्फ विनेश फोगाट से जुड़ा नहीं है। हम यह चर्चा करना चाहते हैं कि इसके पीछे आखिर कौन है? इसी दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो हंगामा तेज हो गया। इसी दौरान सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर नाराजगी जताते हुए कहा, सदन में आपका व्यवहार सबसे खराब है। आप चेयर की ओर चिल्ला रहे हैं। मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूं। अगली बार मैं आपको सदन के बाहर कर दूंगा। आपने चेयर पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की।

इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी सभापति अपनी पीड़ा वक्त करते रहे। उन्होंने कहा, हमने सदन के अंदर अभी सबसे खराब स्थिति को देखा। हमने आपातकाल के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह कैसे शुरू हुआ था। यह सबसे संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने के साथ शुरू हुआ था। जून 1975 में चुनौती थी। अभी भी गंभीर चुनौती है। क्या इस तरह के व्यवहार की कोई सही ठहरा सकता है।

उन्होंने कहा, वो सोचते हैं वो सभी बहुत बुद्धिमान हैं। वो सोचते हैं अकेले वही हैं जिनके दिल को दुख पहुंचा है। हमारी बेटी (विनेश फोगाट) को लेकर पूरा देश दुखी है। चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मैं खुद हूं सभी इस दुख को महसूस कर रहे हैं। लेकिन, इसका लाभ उठाना, इस पर राजनीति करना उस बेटी का अपमान है। उस लड़की को बहुत आगे जाना है।

उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश था कि हरियाणा सरकार ने तुरंत इस बात का एलान किया कि वो उसे सभी सुविधाएं और आर्थिक लाभ देंगे जो पदक विजेता को मिलता है। राज्य सरकार ने उन्हें पदक विजेता के तौर पर सम्मान दिया है। दूसरी ओर इस सदन में क्या हो रहा है? कल जब नेता प्रतिपक्ष ने अपना हाथ उठाया तो मैंने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखीं। मैंने उन्हें एक संदेश भेजा। आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं। उनकी ओर से जवाब आया मैं एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं। क्या इससे विषय का पता चलता है, क्या इससे इसके महत्व का पता चलता है, क्या इससे इसकी अर्जेंसी का पता चलता है? इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नेता प्रतिपक्ष का आशय यह था कि चेयर रबर स्टैंप है।

इसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि माननीय सदस्यगण इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना। अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, यह अमर्यादित आचरण नहीं है, यह हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। यह सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता को रूप में देख रहा है। यह सदन प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को भी यहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां देख रहा है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन की सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं, और जिस तरह से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कितनी गलत टिप्पणी की है।

उन्होंने कहा, मैंने देखा है। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है। यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है, और ये चुनौती इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है, वो इसके लायक नहीं है। ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की है। जयराम जी आप हंसिए नहीं... मैं आपकी आदत जातना हूं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है।सदन में बहुत से वरिष्ठ सदस्य हैं। अब भी उपस्थित हैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से...मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं। पर जो आज मैंने देखा है। जिस तरह का व्यवहार सदस्यों ने किया है। शारीरिक रूप से किया है। जिस तरह का व्यवहार इधर से (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) भी हुआ है। कुछ समय के लिए मैं यहां बैठने में अपने आपको सक्षम नहीं पा रहा हूं।

इससे पहले धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि आप चेयर पर चिल्ला रहे हैं। मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं। क्या कोई इस तरह के आचरण को बर्दाश्त कर सकता है?

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा और प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है। दुर्भाग्य से, हम इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बांट रहे हैं। नड्डा ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हों और जिसके लिए सत्ता पक्ष तैयार हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय और आईओसी ने सभी मंचों पर समाधान का प्रयास किया। ओलंपिक स्पर्धा में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग को आसन की ओर से खारिज किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया।

लोकसभा में पेश किया गया वक्फ बिल

विपक्ष ने कहा- यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ

नईदिल्ली। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। विपक्ष की ओर से बोलते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये संविधान की ओर से दिए धर्म और फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अयोध्या के मंदिर में कोई नॉन हिंदू है, क्या किसी मंदिर की कमेटी में किसी गैर हिंदू को रखा गया है।

वेणुगोपाल ने कहा कि वक्फ भी एक धार्मिक संस्था है। ये समाज को बांटने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह बिल महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनावों के लिए बनाया गया है। आप नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है।

ललन सिंह ने लगाई विपक्ष को फटकार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर सरकार का समर्थन किया है। यह पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ??ललन सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए कहा कि इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक मस्जिद या मंदिर के बारे में नहीं है, बल्कि एक संस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास है।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए, पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी। ये उसका अधिकार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए है। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिखों का कत्लेआम किसने किया था।

ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से कर रहा है, वे मुख्य मुद्दे से भटका रहे हैं। उन्होंने पूछा कि केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस) को बताना चाहिए कि हजारों सिख कैसे मारे गए। किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी को मारा? अब वे अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने के लिए पेश किए गए इस विधेयक में मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रस्ताव है।

अपने उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करने के लिए है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। विधेयक में बोहरा और अगाखानियों के लिए औकाफ के एक अलग बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका में भारत की हार 3 बड़े गुनहगार

नईदिल्ली। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम को एकदिवसीय सीरीज के दौरान हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंकाई टीम ने तीसरे और अंतिम वनडे मैच में जीत दर्ज करते हुए बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ही सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया और 27 साल बाद नया इतिहास रच दिया। टीम इंडिया इस सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ हर मोर्चे पर विफल रही है। भारतीय टीम पहले एकदिवसीय मैच में जीत के करीब जाकर रह गई और मुकाबला टाई हो गया था। इसके बाद अगले दो मैचों में टीम इंडिया को पराजय का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम ने सीरीज गंवा दी।

पहला नाम : टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाने लायक जो पहला नाम है, वह एक ऑल राउंडर का है। इस खिलाड़ी से टीम को खासी उम्मीदें थीं और बैटिंग में यह स्पिनरों को बखूबी खेलता है लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बात शिवम दुबे की हो रही है। बैटिंग में दुबे ने 3 मैचों में महज 34 रन बनाए। गेंदबाजी में उनको एक विकेट मिला।

दूसरा नाम : दूसरा नाम यहाँ विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए हो रही है। ऋषभ पन्त, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बतौर कीपर खेलने के लिए तैयार हैं। ऐसे में केएल राहुल की शायद जगह नहीं होगी। केएल राहुल को टीम से बाहर किया जा सकता है। राहुल ने 2 मैचों में 31 रन बनाए हैं।

तीसरा नाम : तीसरा खिलाड़ी गेंदबाजी विभाग से आता है, जो श्रीलंका दौरे पर खरा नहीं उतर पाया। हालाँकि टी20 फॉर्मेट में इस खिलाड़ी का काम धाकड़ रहा है। श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में दो मैचों में 2 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह का नाम वनडे टीम में फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। टी20 के लिए वह उपयुक्त खिलाड़ी हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 582 अंक टूटा निफ्टी 24,117 पर बंद

नईदिल्ली। गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार नौवीं बार रीपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लेने के बाद इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 581.79 अंक या 0.73 प्रतिशत टूटकर 78,886.22 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 78,798.94 और 79,626.92 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 180.50 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 24,117.00 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,079.70 और 24,340.50 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईटीसी और इंडसइंड बैंक सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे। इसके अलावा, सन फार्मा और एक्सिस बैंक के शेयर भी लाभ में रहे।

लगातार 9वीं बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं

नईदिल्ली। वित्त-वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद गुरुवार सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बैठक के नतीजे घोषित करते हुए बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, लगातार 9वीं बार रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले 18 महीनों से दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि आम आदमी को फिलहाल कर्ज को लेकर कोई राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा, घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई हैं। दूसरी तरफ, दक्षिण-पश्चिमी मानसून से सप्लाई-चैन प्रभावित हुई, उच्च संचयी खरीफ बुआई और जलाशयों के स्तर बढ़ने से खरीफ वाली फसलों के लिए अच्छा मानसून है।

टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा बढ़ाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। वर्तमान में, यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है। दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। दास ने कहा, यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

डिपॉजिट में धीमी वृद्धि चिंता का विषय, नए उत्पाद लाएं बैंक

नईदिल्ली। घरेलू बचत के वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर बढ़ने से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने गुरुवार को बैंकों से कहा कि वे अपने विशाल शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर नवोन्मेषी उत्पादों तथा सेवाओं के जरिये जमा जुटाएं। उन्होंने कहा, '' बैंक बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए अल्पकालिक गैर-खुदरा जमा और देयता के अन्य साधनों का अधिक सहारा ले रहे हैं। जैसा कि मैंने जोर दिया है, इससे बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक नकदी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।'' दास ने कहा कि वैकल्पिक निवेश के रास्ते खुदरा ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं। इसके चलते बैंकों को वित्तपोषण के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जमा वृद्धि कर्ज मे बढ़ोतरी से पीछे है।

विनेश फोगाट ने 53 के बजाय 50 किलोग्राम कैटेगरी लेकर रिस्क लिया!

विनोद पाठक

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट जैसे ही पेरिस ओलंपिक-2024 में वूमेन रेसलिंग की 50 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में पहुंची थीं, देश में एक अलग सा उल्लास छा गया था। गोल्ड नहीं तो सिल्वर पक्का था। चंद घंटों में यह खुशी उदासी में बदल गई, क्योंकि विनेश फोगाट अपनी कैटेगरी में तय वजन से 100 ग्राम अधिक पाई गईं। इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन के नियम बेहद सख्त होते हैं। एक ग्राम वजन भी अधिक होता है तो रेसलर को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट इन नियमों से अनभिज्ञ थीं, क्योंकि एक रात पहले उन्हें पता था कि उनका वजन अधिक है।

फाइनल में जाने से पहले उन्होंने अपना वजन कम करने की कोशिश की थी। विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक-2020 में 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेली थीं, लेकिन पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी क्यों लीं? जबकि महिला रेसलर के लिए वजन कम करना बेहद मुश्किल माना जाता है। क्या विनेश फोगाट ने कैटेगरी बदलकर बड़ा रिस्क लिया? यह ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर विनेश फोगाट के पास ही है।

पहले नियमों की बात करते हैं। महिलाओं की फ्रीस्टाइल रेसलिंग में 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलोग्राम की कैटेगरी होती हैं। मुकाबले से पहले सुबह रेसलर का वजन मापा जाता है। टूर्नामेंट के दोनों दिन रेसलर को अपने वजन के भीतर रहना होता है। यदि रेसलर फाइनल में पहुंचता है तो उसे सुबह अपना वजन कराना होता है। विनेश फोगाट मंगलवार को मुकाबले के लिए जब गईं तो उनका वजन तय मानक से अधिक

था। मंगलवार रात भर विनेश फोगाट ने दौड़, स्किपिंग और साइकलिंग कर अपने वजन को कम करने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहीं। स्वयं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा और विनेश फोगाट के न्यूट्रिशियन दिनशॉ पारदीवाला ने कोशिश की। उन्होंने विनेश के बाल काटे, उसके कपड़े छोटे किए।

भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने एक चैनल से बातचीत में इसका बात का खुलासा किया कि फाइनल में जाने से पहले विनेश फोगाट का वजन दो किलोग्राम अधिक था। कोशिशों के बावजूद विनेश 1.8 किलोग्राम से अधिक वजन कम नहीं कर पाई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने भी स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार फैसला लिया जाता है। एक ग्राम भी वजन ज्यादा हो जाए तो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक खेल है। रियो ओलंपिक-2016 में उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक-2020 में वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलीं, लेकिन पेरिस ओलंपिक में आकर उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना तय किया। यह बात सही है कि 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट रेसलर 53 किलोग्राम की कैटेगरी में आते हैं।

किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक पदक जितना एक बड़ा सपना होता है। देश का नाम ऊंचा होता है। पेरिस ओलंपिक में यदि विनेश फोगाट सिल्वर या गोल्ड जीततीं तो यह उनका ओलंपिक में पहला पदक होता। अब तक वो एशियाई चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। मात्र 100 ग्राम वजन के अंतर से न केवल विनेश फोगाट का सपना टूटा है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों की खुशियां भी एक झटके में उड़ गई हैं।

सही मायने में विनेश फोगाट ने 53 के बजाय 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलकर बहुत बड़ा रिस्क लिया। यदि वो सत्य जानती थीं तो उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए था। पिछले दिनों दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन को लेकर विनेश फोगाट बहुत चर्चा में रहीं। ओलंपिक में विनेश की हार-जीत खेल के बजाय राजनीतिक अखाड़े में बदल गई है। ओलंपिक भले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहे हैं, लेकिन असली कुश्ती भारत में सोशल मीडिया पर खेली जा रही है।

जन दर्शन.....

मुख्यमंत्री ने कहा- रक्षाबंधन का देंगे उपहार

मुख्यमंत्री जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मिलने दो बहनें आईं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले जनदर्शन में आए हैं इसलिए पहले राखी बांधेंगी। रिशी अग्रवाल और सिद्धका गोस्वामी बिलासपुर और बेमेतरा से मुख्यमंत्री के लिए राखी लेकर आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। रिशी ने बताया कि उनके पिता डॉ जे पी वर्मा शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में प्रोफेसर के पद पर थे। उनका निधन हो गया उन्हें अनुकंपा नियुक्ति उनकी शिक्षा के मुताबिक मिले तो अच्छा लगेगा और उन्होंने तृतीय श्रेणी के पद के लिए आग्रह किया।

मिनी गोल्फ में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात

जनदर्शन में 37वें राष्ट्रीय खेल के दौरान मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतकर लौटी महासमुंद निवासी चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलको ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी उपलब्धि से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आगामी 25-30 अगस्त तक दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल वुड बॉल में हिस्सा लेने के लिए वे लोग दक्षिण कोरिया जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने दोनों खिलाड़ियों की हौसल अफजाई करते हुए इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

रीबा के माता-पिता ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ की बालिका रीबा बेन्नी ने न्यूज़ीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूर्व में आयोजित जनदर्शन में सहायता की माँग की थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री साय ने सहृदयता से स्वीकार करते हुए तत्काल सहायता राशि चार लाख रूपये स्वीकृत किया था। उक्त राशि से रीबा बेन्नी न्यूज़ीलैंड पहुँच पायी और वहाँ सिल्वर मेडल अर्जित किया। आज इस खुशी को रीबा के माता-पिता ने मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और सम्मान में उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को श्रीफल भेंट कर सहायता के लिए आभार जताया।

अनुसूचित एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शत प्रतिशत पहुंचे शासन की योजनाएं : डेका

रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, महानिदेशक अरूण देव गौतम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, नक्सल प्रभावित एवं आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, आपदा प्रबंधन की तैयारी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

राज्यपाल डेका ने राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो नक्सली समर्पण कर रहें है उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उपाय करे और प्राथमिकता से उन्हें आश्रय उपलब्ध कराया जाये। इन क्षेत्रों के लोगों को केन्द्र एवं राज्य शासन की शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाये। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से संचार व्यवस्था की जाए ताकि यहां के निवासी दूसरे क्षेत्रों

राज्यपाल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली

के विकास एवं गतिविधियों के बारे में जान सकें।

पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया और पिछले पांच वर्षो में राज्य में होने वाले बड़ी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया।

राज्यपाल ने मानव तस्करी रोकने के लिए किए गए उपायों, नये न्याय अधिनियम लागू करने के लिए पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुलिस को शारीरिक रूप से चुस्त रहना चाहिए और जनता से मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए। पुलिस विभाग में लंबे समय तक पद खाली न रहें और रिक्त पदों पर भर्ती त्वरित रूप से होना चाहिए। राज्यपाल डेका ने अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सी.एस.आर और जिला खनिज न्यास (डी.एम.एफ.फंड) की राशि खर्च की जानकारी। इन क्षेत्रों में नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले शत-प्रतिशत राशि निचले स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री डेका ने राज्य में विशेष कर स्थानीय निकायों में शौचालयों की स्थिति की जानकारी ली।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिलः कांग्रेस करती है तुष्टिकरण की राजनीतिः ओपी चौधरी

रायपुर. वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिसका विपक्ष ने विरोध किया है. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पंडित नेहरू की पीढ़ी में इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार बिल लाया. इसे मुस्लिम समाज के लिए लागू न करके अपिचमेंट की राजनीति की गई. कांग्रेस ने 1966 में संसद में संतों के ऊपर गोली चलाने का काम किया. मनमोहन सिंह से कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर मुस्लिम समाज का हक है. मंत्री चौधरी ने कहा, मुस्लिम अस्पताल बनाने की कल्पना कांग्रेस कर सकती है. मुसलमानों का इलाज होगा, लेकिन बाहर तड़पते हिंदुओं का इलाज नहीं होगा. कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करते आई है. तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को देश की जनता समझ गई है. बीजेपी का स्पष्ट सिद्धांत है, न्याय सभी के साथ और तुष्टिकरण किसी के साथ भी नहीं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान यात्रा निकालेगी, इस पर ओपी चौधरी ने कहा, आपातकाल लगाकर जिस पार्टी ने लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा वो आज संविधान की बात करते हैं. वोट बैंक की राजनीति और अफवाह की राजनीति के लिए इस तरह की बातें करते हैं. 16 अगस्त को कांग्रेस के एसडीएम कार्यालय घेराव पर मंत्री चौधरी ने कहा, गोबर से लेकर गौठान तक में माफिया राज चलाया. जिन्होंने गौ माता और गंगा जल को नहीं छोड़ा, उनकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है.

भाजपा के सहयोग केंद्र में हो रहा समस्याओं का हल

भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में सहायता केंद्र आयोजित की गई है. यहां जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज गुरुवार को वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सहायता केंद्र में उपस्थित रह कर सैकड़ों की संख्या में आए आवेदनों का त्वरित निराकरण किया. इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि यहां सबको विशेष रूप से सुनने और उनकी समस्याओं के निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सहायता केंद्र में संगठन के पदाधिकारी और सरकार के मंत्री उपस्थित रहते हैं. हमारे पास पहुंच रहे आवेदनों और समस्याओं को उनके विभिन्न विषयों को, विकास संबंधी मांगों को पूरा सुना जाता है. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत गुरुवार को यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यालय में आज करीब डेढ़ सौ से अधिक आवेदनों पर तुरंत पहल की गई और समस्याएं और शिकायतें सुनकर उनके विषयों पर नियमानुसार संतोषजनक निष्पादन त्वरित रूप से व्हाट्सएप संदेश भेजकर, फोन कर उन सभी का समाधान तत्काल किया गया.

बाबू भैया की कलम से ✍

बयानः तीन साल में होगा खत्म नक्सल आतंक, केंद्रीय सूची में अब भी 15 जिलों में मौजूद

केंद्र सरकार ने फिर एक बार देश में नक्सल गतिविधियों में लिप्त क्षेत्र की सूची जारी की है। इस सूची में छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बताया गया है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 15 जिलों को नक्सल गतिविधियों का केन्द्र बताया गया है। इस अनुसार देश की सूची में दिए आंकड़ों में 40 प्रतिशत जिले सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस सूची में बस्तर संभाग के सभी सात जिले यानि बस्तर, दंतेवाड़ा,बीजापुर,नारायणपुर,सुकमा,कोंडागांव और कांकेर नक्सल प्रभावित हैं। इस सूची में अब सरगुजा के बलरामपुर को नक्सल गतिविधियों से मुक्त हुआ बताया गया है। इसके स्थान पर बिलासपुर संभाग के मुंगेली को शामिल बताया गया है। इसी तर्ज पर दुर्ग संभाग के कबीरधाम,राजनांदगांव मोहला- मानपुर,अम्बागढ़ चौकी,और खैरागढ़ को नक्सल गतिविधियों से प्रभावित बताया गया है। रायपुर संभाग के धमतरी,गरियाबंद,महासमुंद,जिले भी नक्सलवाद की चपेट में बताए गए हैं। झारखंड के 5 जिले,ओड़िसा के 7 जिले , महाराष्ट्र-तेलंगाना के 2-2 जिलें नक्सल प्रभावित हैं। मध्यप्रदेश के 3 जिले भी प्रभावित बताए गए हैं। जबकि मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में गर्व के साथ बताया था कि उनका प्रदेश डकैत समस्या के साथ-साथ नक्सल गतिविधियों से भी पूरी तरह मुक्त हो चुका है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने फर्जी आंकड़ों के सहारे यह बात की थी। एक बात यह भी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ में तीन साल में नक्सल वाद को जड़ से समाप्त करने की घोषणा करके उसे एक जुमला बना दिया है। जो आंकडे केंद्र ने जारी किये हैं वे तो अमित शाह के बयानों के विपरीत जा रहें है। दरअसल सारे बयान बेकार साबित हो रहे हैं। नक्सलवाद समाप्त नहीं होता ,बल्कि कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। समय के साथ फिर से लौट लौट कर यह समस्या फिर अपना सिर उठा लेती है और किसी नई घटना के साथ सामने आ जाती है। यह माहौल देश-प्रदेश में 4 दशकों से बना हुआ है ,अनेक केंद्रीय गृह मंत्री आये सबने अपने अपने ढंग से जाबांजी वाले बयान दिए-गरजे। किसी ने जवानों की दी गई शहीदी पर कहा ,जवानों की शहीदी बेकार नहीं जाने देंगें। नक्सलियों की मांद में घुस कर मारेंगें,किसी ने कहा घर में घुस के मारेंगें, हमें उनकी चुनौती स्वीकार है,कभी कहा सेना का प्रयोग करेंगें। यूपीए की सरकार के समय तत्कालीन गृह मन्त्री पी.चिदंबरम ने रायपुर में कहा था इन्हें नहीं छोड़ेंगे,राजनाथ सिंह ने दो घटनाओं के दौर में कहा था कि हमें नक्सलियों की चुनौती स्वीकार है। बयान रायपुर में दिए गए दिल्ली जाकर मंत्री ही नही बयान भी मौन हो गए। बयान आते रहे ,नक्सल गतिविधियां होती रही। ज्यादा पुराने आंकड़ों पर ना जाते हुए देखिए 15 मार्च 2007 को बीजापुर के एक घटना में 55 जवान शहीद हुए,बयान यही आया,नहीं छोड़ेंगे,शहीदी बेकार नहीं जाएगी। दिल्ली जाकर शांति हो गई ।तीन साल बाद 16 अप्रेल 2010 को ताड़मेटला में सर्वाधिक 76 जवानों का एक साथ एक घटना में नक्सलियों ने सामूहिक नरसंहार किया। वही बयान फिर आया,दिल्ली जाकर फिर शांति। एक माह बाद 17 मई 2010 में दंतेवाड़ा में 36 जवानों की शहीदी हुई। वही बयान,दिल्ली जाकर फिर शांति। फिर 29 जून 201 0 को नारायणपुर में एक घटना में 27 जवान शहीद हो गए। फिर वही बयान,दिल्ली जाकर मौन। 25 मई 2013 को प्रदेश में भीषण व वीभत्स हत्याकांड घटित हुआ जिसमे कांग्रेस के लगभग सभी अग्रणी वरिष्ठ नेताओं को मार दिया गया। सुरक्षा जवानों समेत कुल 30 नेताओं की मौत हुई। बातें तो खूब हुई पर सब कुछ शांत। शहीद हुए कांग्रेस नेताओं के परिजन आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। घटनाएं व बयानबाजियां यहीं खत्म नहीं हुई। सुकमा के भेज्जी में 11 मार्च 2017 को 12 जवान,सुकमा के बुर्कापाल में 24 अप्रैल 2017 को 25 जवान,सुकमा के किस्टाराम में 9 जवान शहीद हुए। सभी इन घटनाओं के बाद वही कुछ दोहराया गया,जो हमेशा दोहराया जाता था। मदनवाड़ा की दर्दनाक घटना जिसमे एक आपीएस शहीद हुआ कई जवान मारे गए,हथियार लूटे गए। बात वहीं की वहीं घूमती है। इन सब घटनाओं में बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए इसमें कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन जवानों व नेताओं का हताहत होना प्रदेश के शरीर पर कोढ़ की तरह का दाग बन कर रह गया। एक बडा बयान आया कि तीन साल में नक्सलवाद देश से समाप्त कर देंगें। 11 साल हो गए वो तीन साल पूरे नहीं हुए हैं। आमजनता बयानबाजी के मायने ढूंढ रही है। एक बात जरूर हुई है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान भाजपा सरकार थोड़ी कड़ाई बरतते दिखाई दे रही है। नक्सली बड़ी संख्या में मारे भी गए हैं और मुख्यधारा में लौटे भी हैं। सरकार सख्ती दिखा जरूर रही है। पर इतने से यह कहना अतिशियोक्ति होगी कि नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। यह देखा गया है कि जब जब नक्सल गतिविधिया थमी सी दिखती है , उस दौर में नक्सली अपनी मजबूती बढ़ाने में लग जाते हैं। लंबे अरसे के बाद बड़ी वारदात के साथ सामने आते हैं।वर्तमान सरकार ने आपसी बातचीत के रास्ते भी खोलते हुए सीधा आह्वान भी किया है कि हम किसी भी माध्यम से नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। इस मामले पर नक्सलियों की ओर से सकारात्मक जवाब का अभी तक अभाव दिखाई दे रहा है।माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे ही सही यह समस्या समाप्त होने लगी है। हमारे सुरक्षा बल पूरी ताकत के साथ ना सिर्फ वहां अपनी मौजूदगी का अहसास करा रहै हैं,जहां तक अब तक सुरक्षा बलों की व सरकार की पहुंच नहीं के बराबर थी। कहा जा रहा है की अब अबूझमाड़ अबूझ नहीं रहा। अब शायद वह समय आ रहा है, जब नक्सल क्षेत्र में सांझा प्रयास से केंद्र व राज्य मिलकर तथा सभी दलों को सहमत कराकर इस आतंकी समस्या का समाधान खोजने की दिशा में बढ़ सकते हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से प्रकरणों पर समीक्षा की गई

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बीते दिनों विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक निवास कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम, एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों की आज समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आरोपी रोशन ने होटल में 5 घंटे पत्नी संग बिताए

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को पुलिस ने इलाज के बहाने सेंट्रल जेल से बाहर निकाला और 5 घंटे तक वेनिंगटन होटल में रहने दिया. इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल उसके बच्चों को बाहर घुमाता रहा. यह मामला 2 अगस्त का है. इसका वीडियो वायरल होते ही जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है. बताया जा रहा कि आरोपी रोशन चंद्राकर जब अपनी पत्नी से होटल में मिल रहा था उस दौरान जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को पंडरी सिटी सेंटर माल घूमता रहा. उसने वर्दी के ऊपर टीशर्ट पहन कर रखा था. मामला सामने आने के बाद डीजी जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है. उन्होंने आरोपी जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही प्रदेश के सभी जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि इलाज के दौरान बंदियों को बाहर ले जाकर होटल में चाय-नाश्ता कराने, मोबाइल देने जैसी बातें सामने आ रही है.

टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बदल गई बच्ची!

बिलासपुर। रायपुर के पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए जगदलपुर निवासी दंपती ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंटर के चिकित्सकों के साथ राज्य सरकार और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. दरअसल, जगदलपुर के बड़े बचेली निवासी उषा सिंह और उनके पति अशोक सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि दंपती पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में दो साल से इलाज करा रहे थे, जिसके बाद उन्हें जुड़वा बच्चे बेटा-बेटी हुए. लेकिन बाद में दो बच्चियां रख दी गई. इस बात की शिकायत उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से की, तो कोई सुनवाई नहीं की गई. दोनों बच्चियों का डीएनए करवाने पर एक बच्ची का डीएनए नहीं मिला. मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने राज्य सरकार, रायपुर के पुलिस अधीक्षक और पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेन्टर की डॉ. नीरज पहलाजानी और डॉ.समीर पहलाजानी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने कहा है.

महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता

रायपुर। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए संचालित सट्टेबाजी के अवैध कारोबार पर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुंबई में दबिश देकर पाँच सटोरियों को गिरफ्तार किया है। यह सट्टेबाजी का कारोबार बिलासपुर और जबलपुर के सटोरिए मिलकर संचालित कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, मुंबई के जूहू स्थित एक होटल में सट्टेबाजी चल रही थी। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां एक हफ्ते तक निगरानी की और अंततः होटल के कमरे पर छापा मारकर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सटोरियों में से दो बिलासपुर और तीन जबलपुर के निवासी हैं। इनके नाम रोहित पंजवानी (चकरभाठा-बिलासपुर), सागर चेतवानी (सरकंडा-बिलासपुर), कपिल मेहरा (जबलपुर), शेखर कुकरेजा (जबलपुर) और अनमोल पथरिया (जबलपुर) बताए गए हैं। रायपुर के आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष कुमार सिंह की निगरानी में इस मामले पर कार्रवाई की गई।

सलमान के बांग्लादेश वाले बयान पर वर्मा ने जताया विरोध

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मध्यप्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होने वाले बयानों को कांग्रेस के नितांत शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और नए-नए अराजकतावादी राजनीतिक चरित्र का परिचायक बताया है। श्री वर्मा ने कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान ही कांग्रेस अपने अनुकूल परिणाम नहीं आने पर देश में आग लगने जैसे धमकी भरे बयान देती रही और अब चुनावों में करारी शिकस्त खाने के बाद देशविरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर कांग्रेस अपने इसी टूलकिटिया एजेंडे पर काम कर रही है। वर्मा ने कहा कि मप्र कांग्रेस के नेता वर्मा द्वारा यह कहा जाना कि, जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास में लोग घुसे हैं, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री श्री मोदी की नीतियों की वजह से उनके आवास में भी घुसेंगे, यह बहुत आपत्तिजनक बयान है। इसी तरह का बयान खुर्शीद ने भी दिया है। कांग्रेस के केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व के इन बयानों पर मौन पर हैरत जताते हुए श्री वर्मा ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि मप्र कांग्रेस नेता वर्मा पर राहुल गांधी ने तो कार्रवाई नहीं की, क्या भूपेश बघेल, चरणदास महंत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी ऐसे बयानों से सहमति जताते हैं? श्री वर्मा ने दोटू कहा

जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है

भ्रष्टाचारियों को बचाने भूपेश ने सारी हदें पार की : मूणत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाला मामले को लेकर हो रहे खुलासों पर कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार किस कदर रचा-बसा है, इसका जीवंत प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर किए गए उस दावे से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि आरोपित रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को 16 अक्टूबर, 2019 में अग्रिम जमानत देने वाले हाई कोर्ट के एक तत्कालीन जज उनके (आरोपितों के) संपर्क में थे। श्री मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने वाली कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार ने पहले तो जनता का धन लूटा, उनका अनाज लूटा और बाद में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर सबूत से छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, विधायक व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि जिस प्रकार जाँच एजेंसियाँ सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को सामने रख रही हैं, वे हैरान करने वाने हैं। पीडीएस घोटाले के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया और इसके लिए किस हद तक भूपेश बघेल की सरकार गई थी, यह अब आईने में साफ नजर आने लगा है। भ्रष्टाचारियों से कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार का बड़ा गहरा नाता रहा है, कई मामलों में तो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भ्रष्टाचार के आरोपितों की खुलकर वकालत तक करते नजर आए थे। चूँकि भ्रष्टाचार के इन मामलों में कांग्रेस नेताओं और भूपेश सरकार की पूरी संलिप्तता रही है इसलिए भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से बचाने का प्रयास किया गया। श्री मूणत ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल के इन तमाम घोटालों के सत्य और तथ्य अब सामने आ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचारियों से जुड़े लोग जजों के संपर्क में थे और जज से संपर्क बनाने में उनके नौकरशाह भाई और तत्कालीन एजी ने लाइजनर की भूमिका निभाई थी।

मूणत ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात कहती रही है और अब ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामा में दावा किया गया है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी।

मुकदमे को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। श्री मूणत ने कहा कि ईडी के हलफनामे से स्पष्ट है कि व्हाट्स एप संदेशों के आदान-प्रदान से पता चला है कि जज की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा को भेजा गया था।

प्रदेश में खुलेगा एलएनआईपीई का क्षेत्रीय संस्थानः वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा के साथ खेलों में विशेषज्ञता हासिल करने शीघ्र ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) ग्वालियर की तर्ज पर क्षेत्रीय संस्थान प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। एलएनआईपीई सेंटर के लिए नवा रायपुर के तेन्दुआ में 120 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे राजस्व विभाग के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले इस एलएनआईपीई सेंटर को भारत सरकार वित्तीय सहायता देगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा और ग्वालियर के राष्ट्रीय

संस्थान के कुलपति प्रोफेसर इंदू बोरा के साथ हुई बैठक में नवा रायपुर के तेंदुआ में एलएनआईपीई सेंटर स्थापित करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। एलएनआईपीई के क्षेत्रीय संस्थान में प्रति शैक्षणिक सत्र में 1000 छात्र शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकेंगे। यह संस्थान पूर्णतः आवासीय होगा। इसके लिए तेन्दुआ में 120 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे राजस्व विभाग के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है। एल.एन.आई.पी.ई. की कुलपति प्रोफेसर इंदू बोरा ने बताया कि अगले सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एण्ड स्पोर्ट्स भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.